RNI No. DLHIN/25/A2321

DD

दिव्य दिल्ली

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

वर्ष: 01, अंक: 26, पृष्ठ: 08

infodivyadelhi@gmail.com

रविवार, 05 अक्टूबर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi

तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री

सूयोदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को पीएम का तोहफा

राजेश चौहान
नई दिल्ली

कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को देश के युवाओं के लिए योजनाओं-परियोजनाओं के अनावरण की झड़ी लगाई तो चुनावी राज्य बिहार के युवा खास तौर पर सरकार के प्यार में सराबोर होते दिखाई दिए। केंद्र-राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का शुभारंभ करते हुए राज्य का अतीत याद दिलाते हुए राजद के शासनकाल को कुशासन बताया और नीतीश कुमार नेतृत्व वाली राजग सरकार की सराहना की।

कांग्रेस पर पीएम मोदी का कटाक्ष

जननायक कपूर्री ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर कटाक्ष किया- जरा चोकन्ने रहिए, ये जननायक पद कपूर्री ठाकुर से ही है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागृत रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कपूर्री ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए।

पीएम के कटाक्ष को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि तमाम कांग्रेस नेताओं ने अब राहुल को जननायक की उपाधि दे दी है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही बिहार की बहनों के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बहुत भव्य कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर मिला था। आज बिहार के युवाओं के सशक्तीकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है।

आत्मनिर्भर भारत की कार्यशाला हैं आइटीआइ

पीएम ने कहा कि अच्छे संस्थानों के साथ-साथ नीतीश सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को ब्याजमुक्त कर दिया गया है। ये बिहार सरकार का निर्णय है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए स्कालरशिप भी 1800 से बढ़ाकर के 3600 रुपये कर दी गई है। पीएम ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयंसहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया, जिसमें पांच लाख स्नातकों को दो वर्ष तक प्रतिमाह एक हजार रुपये दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी आइटीआइ इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो हैं ही, ये आत्मनिर्भर भारत की कार्यशाला हैं।

आईटीआई पटना में भी इंफ्रास्टक्चर के विस्तार का काम शुरू

आज बिहार के युवाओं के लिए भी इस मंच से अनेक योजनाएं और परियोजनाएं समर्पित हुई हैं। बिहार में नया कौशल विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार की शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है।

आईटीआई पटना में भी इंफ्रास्टक्चर के विस्तार का काम शुरू

उन्होंने कहा कि आईटीआई पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। आज भी बिहार में कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम आरंभ हुआ है। एनआइटी पटना के बिहटा कैंपस को भी अब होनहार विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए एकेडेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है।

यूके के प्रधानमंत्री कीर आठ को दो दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर यूनाइटेड किंगडम (यूके) के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर आठ अक्टूबर को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। यह प्रधानमंत्री स्टार्मर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री 09 अक्टूबर को मुंबई में मुलाकात करेंगे और विजन 2035 के तहत भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं में प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस 10 वर्षीय रोडमैप में व्यापार और निवेश, तकनीक और नवाचार, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन-से-जन संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

गिल बने भारतीय टीम के वनडे कप्तान, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित-कोहली की वापसी

नई दिल्ली

शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह भारतीय क्रिकेट टीम का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। गिल 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम का नेतृत्व करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा को बल्लेबाज के रूप में टीम में चुना गया है और विराट कोहली के साथ वह मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 26 वर्षीय गिल अब टेस्ट और वनडे में कप्तान और टी20 टीम के उप-कप्तान के

रूप में तीनों प्रारूपों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभा रहे हैं। 38 वर्षीय रोहित दिसंबर 2021 से भारत के पूर्णकालिक वनडे कप्तान थे। कुल मिलाकर, उन्होंने 56 वनडे मैचों में भारत का नेतृत्व किया, जिसमें 42 जीते, 12 हारे, एक टाई और एक बेनतीजा रहा। उन्होंने कार्यवाहक कप्तान के रूप में भारत को 2018 एशिया कप खिताब दिलाया और फिर पूर्णकालिक कप्तान के रूप में 2023 एशिया कप खिताब दिलाया। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। उनके कार्यकाल का समापन भारत द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के साथ हुआ।

इस गर्मी में भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले मई में रोहित के टेस्ट प्रारूप से संन्यास लेने के बाद गिल भारत के टेस्ट कप्तान भी बन गए थे। टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज में गिल ने भारत को इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ कराया।

गुरु गोबिंद सिंह की पादुकाएं जोड़े साहिब अब तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा को सौंपी जाएंगी

नई दिल्ली

दसवें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह और माता साहिब कौर की पवित्र पादुकाएं जोड़े साहिब अब उनके जन्मस्थान तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा को सौंपी जाएंगी। पिछले 300 साल से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का परिवार गुरु की पादुकाओं की सेवा कर रहा था।

इस संबंध में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही ने शनिवार को यहां

एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली से पटना तक जोड़े साहिब को श्रद्धा के साथ लेकर जाने के लिए एक भव्य नगर कीर्तन यात्रा आयोजित की जाएगी। पुरी ने बताया कि उनके परिवार को तीन सौ वर्ष पूर्व स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी से इन पवित्र अवशेषों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके पूर्वज गुरु महाराज की प्रत्यक्ष सेवा में थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु साहिब ने परिवार को इन पादुकाओं की सेवा और संरक्षण की आज्ञा दी थी। पुरी ने कहा कि उनके चचेरे भाई और अंतिम संरक्षक सरदार जसमीत सिंह पुरी के निधन के बाद परिवार ने निर्णय लिया कि जोड़े साहिब को अब ऐसे स्थान पर रखा जाए, जहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु मत्था टेक सकें। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से इन अवशेषों की बारीकी से जांच कराई गई।

उन्होंने कहा कि चूंकि यह बहुत ही ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य का अवशेष है इसलिए सांस्कृतिक मंत्रालय ने कार्बन-14 परीक्षण करवाया।

विद्वानों ने आरएसएस के कार्यों का किया उल्लेख बताया इतिहास

नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में दो दिवसीय समग्र संघ साहित्य परिचर्चा का आयोजन नेहरू नगर स्थित पीजीडीएवी महाविद्यालय में किया गया। परिचर्चा का उद्घाटन शनिवार को हुआ। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की। मुख्यमतिथि के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर के पूर्व कुलाधिपति डॉ. बलवंत जानी उपस्थित रहे। राजीव तुली भी मंच पर मौजूद थे।

भारत-फ्रांस के बीच रक्षा साझेदारी की मजबूती पर जोर

नई दिल्ली

भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (एफएसएफ) के बीच 22वीं एयर स्टाफ वार्ता का तीन दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इन चर्चाओं में संयुक्त प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, विचारों का आदान-प्रदान, पेशेवर सैन्य शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। चचाओं का उद्देश्य संचालनात्मक समन्वय को मजबूत करना और दोनों वायु सेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना

था। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल एसके तलियान और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के ब्रिगेडियर जनरल निकोलस चांबाज ने की, जो उच्च स्तर की भागीदारी और गहरे रक्षा सहयोग के प्रति आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एयर स्टाफ वार्ता भारत और फ्रांस के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे वे आपसी सहयोग को बढ़ा सकते हैं, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान कर सकते हैं और एयरोस्पेस और रक्षा में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और विकसित कर सकते हैं।

भारत व फ्रांस के बीच एक मजबूत रक्षा साझेदारी

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत व फ्रांस के बीच एक मजबूत और ठोस रक्षा साझेदारी है। इसमें आत्मनिर्भरता का तत्व बढ़ रहा है।

दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा वार्षिक रक्षा संवाद (रक्षा मंत्री स्तर) और रक्षा सहयोग पर के तहत की जाती है।

'अब बात करने को कुछ नहीं, हथियार डालने ही होंगे: शाह

अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक हथियार डालो, वरना सुरक्षा बल देंगे करारा जवाब

नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। राज्य के बस्तर में अमित शाह ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने बस्तर ज़िले के मुख्यालय जगदलपुर में 'बस्तर दशहरा लोकोत्सव' और 'स्वदेशी मेला' को संबोधित भी किया, जहां से उन्होंने नक्सलियों को आखिरी चेतावनी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नक्सलियों को अब हथियार डालने ही होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खतरे को अलविदा कहने के लिए 31 मार्च, 2026 की समय सीमा तय की गई है।

'अब बात करने के लिए कुछ बचा ही कहां है?'

अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नक्सलियों के साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की लाभदायक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को स्वीकार करने के बाद उन्हें (नक्सली) हथियार डालने होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने (नक्सलियों से) बातचीत का आह्वान किया है।

मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार, दोनों ही बस्तर और सभी नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब बात करने की क्या बात है? एक आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लागू की गई है। आगे आइए और अपने हथियार डाल दीजिए।

'शांति भंग करने वालों को मिलेगा करारा जवाब'

अमित शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि हथियारों के बल पर बस्तर की शांति भंग करने वालों को सुरक्षा बल करारा जवाब देंगे। शाह ने का कि दिल्ली में कुछ लोग वर्षों से यह गलत सूचना फैलाते रहे हैं कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई के लिए हुआ था। लेकिन मैं अपने आदिवासी भाइयों को बताने आया हूँ कि पूरा बस्तर विकास से वंचित रहा है। इसका मूल कारण नक्सलवाद है।

पाक सीमा पर तैनात होंगी एके-630, एक मिनट में तीन हजार राउंड करती है फायर

नई दिल्ली

पाकिस्तान सीमा से सटे आबादी वाले इलाकों और आस्था के केंद्रों को सुरक्षा देने के इरादे से मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारतीय सेना ने एक स्वदेशी कंपनी से छह एके-630 एमएम बंदूकें खरीदने की तैयारी की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले सबक पर काम करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब में नागरिक ठिकानों और धार्मिक इमारतों पर सीधे हमले किए थे। आगे ऐसा न होने देने के लिए सेना पहले से तैयारी कर लेना चाहती है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि सेना वायु रक्षा (एएडी) ने एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआइएल) के साथ छह एके630 एयर डिफेंस गन सिस्टम की खरीद के लिए एक आरएफपी (रिक्वेस्ट फार प्रपोजल) जारी किया है। ये एक 30 मिमी मल्टी-बैरल मोबाइल एयर डिफेंस गन सिस्टम है जिसमें लगातार हाई लेवल की फायरिंग की जा सकती है। बंदूक प्रणाली को एक ट्रेलर पर लगाया

जाएगा और हाई मोबिलिटी वाहन से ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एके630 का उपयोग यूआरएएम (ड्रोन, राकेट, तोपखाने और मोर्टार) से पैदा हुए खतरे को विफल करने के लिए किया जाएगा। इसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के निकट स्थित प्रमुख आबादी वाले क्षेत्रों और आस्था के केंद्रों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ये गन सिस्टम 3000 राउंड प्रति मिनट की दर से चार किलोमीटर तक लक्ष्य भेद सकता है। इसमें सभी मौसमों में काम करने वाले इलेक्ट्रो-आप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा होगा, जो किसी भी मौसम में लक्ष्य की पहचान कर सकता है। इसे सुदर्शन चक्र कवच के तौर पर विकसित किया जा रहा है और इसे पूरे वायु रक्षा संरचना से जोड़ा जाएगा।

कोचिंग कल्चर खत्म करने की दिशा में केंद्र की बड़ी पहल

पीएम ई-विद्या के जरिए घर बैठे बच्चे कर सकते हैं पढ़ाई

नई दिल्ली

आपका बच्चा यदि स्कूल में है और आप उसके ट्यूशन और कोचिंग पर हर महीने एक बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं तो अब आप इससे बच सकते हैं। आपके बच्चे को कोचिंग से बेहतर शिक्षा अब घर बैठे ही पीएम ई-विद्या के जरिए मिल सकती है। केंद्र सरकार ने स्कूलों बच्चों के बीच तेजी से बढ़ी कोचिंग संस्कृति को खत्म करने की दिशा में यह अहम पहल की है। जिसमें बच्चों को बालवाटिका से बारहवीं तक के सभी विषयों की अध्ययन सामग्री अब पीएम ई-विद्या के तहत शुरू किए गए टीवी चैनलों और मोबाइल एप पर मुहैया होगी। जिसे बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार देख और पढ़ सकते है।

चैट के जरिए मिलेंगे सवालों के जवाब

पढ़ाई के दौरान छात्रों के मन में उससे जुड़े किसी तरह के सवाल होंगे, तो चैट के जरिए उसके भी जवाब पा सकेंगे। यह सब बिल्कुल मुफ्त होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की देखरेख में स्कूली बच्चों के लिए शुरू हुई इस मुहिम में प्रत्येक कक्षा के लिए एक समर्पित टीवी चैनल के साथ अब एक मोबाइल एप भी तैयार किया है। जिसको आइओएस और एनड्राइड दोनों तरह के मोबाइल फोन में डाउनलोड किया जा सकता है। इनमें बालवाटिका यानी प्री-प्राइमरी के लिए भी पहली बार एक समर्पित चैनल और मोबाइल एप बनाया गया है।

क्या इस एप की खास बात

खासबात यह इससे जुड़ी अध्ययन सामग्री को तैयार करने या छात्रों की मदद के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अलग-अलग विषयों के देश के श्रेष्ठ शिक्षकों को लगाया गया है। एनसीईआरटी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक मोबाइल एप शुरू होने के करीब दो सप्ताह में एक करोड़ छात्र पीएम ई-विद्या एप से जुड़ गए हैं। वैसे तो इसका लक्ष्य स्कूलों में पढ़ने वाले सभी 25 करोड़ छात्रों तक पहुंचने का है। खासकर दूरदराज और पिछले क्षेत्रों के बच्चों तक पहुंचने पर सबसे अधिक फोकस है। एप के जरिए छात्र अपनी कक्षाओं से जुड़ी अध्ययन सामग्री को कभी भी देख सकेंगे।

मध्य प्रदेश में उङ्क'श्रि सिरप पर लगा बैन

भोपाल
तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। इस सिरप पर पाबंदी लगाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त चेतावनी जारी की है। सीएम मोहन यादव का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सिरप के अलावा कंपनी के सभी प्रोडक्ट को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। दरअसल कोल्ड्रिफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा में भी बच्चों की जान चली गई। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, "छिंदवाड़ा में उङ्क'श्रि सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है।"
सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है।

दोषियों को नहीं बख्शेंगेः मोहन **यादव**
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।" छिंदवाड़ा में सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है।

कई बच्चों की हुई मौत
बता दें कि तमिलनाडु में पहले ही इस सिरप को बैन कर दिया गया है। कोल्ड्रिफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसपर एक्शन लेते हुए एमपी में भी इस सिरप को बैन कर दिया गया है।

पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनाएं वैज्ञानिक पद्धति : योगी

राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास में राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नलकूपों से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और वाटर कंजर्वेशन की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा का मौसम इसके लिए सबसे उपयुक्त है। इससे भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी और डार्क जोन वाले क्षेत्रों में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाण सागर, मध्य गंगा जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा कर उसमें कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के सशक्त क्रियान्वयन से ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री ने तराई क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि रिजर्व वायर को डिसिल्ट कर उसे पुनर्जीवित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। साथ ही, कटान रोकने के लिए सिल्ट का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नलकूपों का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जाए। इससे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, किसानों की लागत घटेगी और उन्हें आधुनिक तकनीक आधारित सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

केवल फाइलों तक सीमित न रहें वरिष्ठ अधिकारी, धरातल पर उतरकर परियोजनाओं की देखें प्रगति: मुख्यमंत्री

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आवास विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के अवस्थापना और शहरी विकास कार्यों को नए स्तर पर ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी केवल फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर उतरकर परियोजनाओं की प्रगति देखें और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों को आगे बढ़ाएं प्राधिकरण मास्टर प्लान बनाते समय चयन प्रक्रिया को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाएं ताकि योजनाएं व्यवहारिक तौर पर धरातल पर उतर सकें।

मलिन बस्तियों का कायाकल्प जरूरी: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में शहरों के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्य नियोजित ढंग से और समन्वित रूप में किए जाएं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग कार्य करने से योजनाओं में अनावश्यक देरी होती है। इसलिए सभी विभाग मिलकर साझा कार्ययोजना बनाएं और समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन करें। मलिन बस्तियों के विकास पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क कनेक्टिविटी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकासी व्यवस्था (ड्रेनेज सिस्टम) को और मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रत्येक शहर में ऐसी नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रेनेज सिस्टम के सुधार और नई व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि नागरिकों को बरसात के समय किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। यहां साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क कनेक्टिविटी, कूड़ा कलेक्शन और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए।

चेकडैम, तालाब और ब्लास्टकूप निर्माण को बनाएं जनांदोलन: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (लघु सिंचाई) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जल संकट आज हमारी सामूहिक चिंता का विषय बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप वर्षा जल को रोककर धीरे-धीरे उसे भूमि में समाहित होने देते हैं। यह केवल स्थानीय प्राथमिकता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप केवल पानी रोकने की व्यवस्था नहीं बल्कि समेकित जल प्रबंधन है, जो बड़े बांधों की तुलना में यह काफी किफायती है। उन्होंने निर्देशित किया कि एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर जनांदोलन बनाते हुए चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विभिन्न भागों स्थानीय, बरसाती नदी, नालों में विभाग की ओर से अद्यतन 6,448 चेकडैमों का निर्माण किया जा चुका है। प्रत्येक चेकडैम से औसतन 20 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार निर्मित चेकडैमों से कुल 1,28,960 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई है और हर साल 10 हजार हेक्टेयर मीटर से अधिक भूजल रिचार्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से अन्नदाता किसान वर्ष में दो से तीन फसल लेने में सक्षम हुए हैं।

'जुबीन गर्ग को जहर दिया गया', सिंगर के दोस्त का खुलासा; लगाया साजिश का आरोप

नई दिल्ली
मशहूर सिंगर और अइकन जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानु महांता ने उन्हें जहर देकर मार दिया और इसे हादसा बताने की साजिश रची। गवाह के रूप में दर्ज बयान में गोस्वामी ने कहा कि जुबीन की मौत से पहले मैनेजर शर्मा का व्यवहार संदिग्ध था। मैनेजर पर पहले से ही त्र्क्षक दर्ज हैं, उस पर हत्या, आपराधिक साजिश और गैर-इरादतन हत्या जैसे गंभीर गैर-जमानती आरोप लगे हैं।

क्या है आरोप?
गोस्वामी ने बताया कि सिंगापुर में पैन पैसेफिर होटल में शर्मा उनके साथ रह रहे थे। यॉट यात्रा के दौरान मैनेजर ने यॉट के कैप्टन से जबरन यॉट का कंट्रोल ले लिया, जिससे नाव बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सबकी जान खतरे में पड़ गई। गोस्वामी ने दावा किया कि शर्मा ने असम एसोसिएशन (सिंगापुर) के सदस्य तन्मय फुकन को कहा कि वे ड्रिंक की व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि जब जुबीन सांस लेने के लिए जूझ रहे थे।

प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं से किया संवाद, नीतीश ने राज्य के विकास में योगदान के लिए दिया धन्यावाद

पटना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के टॉपर्स को सम्मानित किया। उन्होंने कौशल दीक्षांत समारोह-2025 के दौरान 62 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े। कार्यक्रम में पुनर्निर्मित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ, वर्ग 9-10 के 25 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 450 करोड़ रुपये की छात्रवृति राशि का हस्तांतरण, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये 'बिहार युवा आयोग' का शुभारंभ, 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' के लाभुकों को राशि का वितरण, भारत रत्न जननायक कपूर्री ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन एवं एनआईटी, पटना के बिहटा कैंपस का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। साथ ही 'पीएम - उषा अभियान' के तहत बिहार के चार विश्वविद्यालयों- पटना विश्वविद्यालय, पटना, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना में नई शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाओं का शिलान्यास तथा नवचयनित 3942 युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की ओर से राज्य के युवाओं के लिये किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।

नड्डा ने दी हिमाचल को बड़ी सौगातें, केंद्र से मिली 843 करोड़ की मदद: बिंदल

शिमला
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी गई अनेक सौगातें प्रदेश की जनता के लिए राहतभरी हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रवास के दौरान नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वह सराहनीय है। डॉ. बिंदल ने शनिवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले हिमाचल सरकार को 843 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जबकि गत माह प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान आपदा राहत के लिए 1500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिमाचल की हर जरूरत पर संवेदनशीलता से काम कर रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नड्डा के प्रयासों से हिमाचल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी बड़ी सौगात मिली है। लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत से बने इस संस्थान में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं, जिससे प्रदेश की जनता को अब बेहतर इलाज अपने ही राज्य में उपलब्ध हो रहा है। बिंदल ने कहा कि यह कार्य असंभव को संभव करने जैसा है और हिमाचल के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि नड्डा ने प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और मातृ-शिशु अस्पतालों के लिए 123 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की है। वहीं, बिंदल ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयुष्मान भारत जैसी गरीबों के हित की योजना का लाभ हिमाचल में सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद कर गरीबों पर कुठाराघात किया है, जो निंदनीय है। डॉ. बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्व में भी चिकित्सा कॉलेजों, मातृ एवं शिशु अस्पतालों तथा कैंसर अस्पतालों के निर्माण के लिए भारी भरकम राशि दी थी, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार उनका सही उपयोग नहीं कर रही है।

एनआइआरएफ में होगी निगेटिव मार्किंग: केंद्र सरकार

नई दिल्ली
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआइआरएफ) में जल्द ही कई मानदंडों के लिए निगेटिव मार्किंग शुरू की जाएगी। इनमें वापस लिए गए शोध पत्र और खराब शोध पत्रों से उद्धरण शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनआइआरएफ के दसवें संस्करण की घोषणा की है। अपनी स्थापना के बाद से एनआइआरएफ में कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं रही है। एनआइआरएफ का प्रबंधन करने वाली एजेंसी नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड (एनबीए) के अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा, "पहली बार शोध में गलत तरीकों के इस्तेमाल और आंकड़ों के गलत प्रस्तुतीकरण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रैंकिंग पद्धति में औपचारिक रूप से दंड को शामिल किया जा रहा है। निगेटिव मार्किंग प्रणाली जल्द ही घोषित की जाएगी और मसौदा मानदंड तैयार किए जा रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि कई संस्थानों में दो-तीन वर्षों से बड़ी संख्या में शोध पत्र वापस लिए जा रहे हैं। इन संस्थानों की विश्वसनीयता एक मुद्दा है। जब तक हम निगेटिव मार्क्स नहीं देंगे, लोग इसे ठीक नहीं करेंगे। एनआइआरएफ में पांच व्यापक मानदंडों के आधार पर शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है।

कानून की धाराएं कानून तोड़ने वालों पर समान रूप से होनी चाहिए लागू : संजय

सुलतानपुर
उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून की धाराएं सभी कानून तोड़ने वालों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए, लेकिन देश की सरकार चुनिंदा तरीके से काम कर रही है। उन्होंने बुलडोजर नीति पर भी निशाना साधा और कहा कि इस नीति पर खुश होने वाले लोग अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। श्री सिंह ने वाराणसी में संत रविदास गेट के सामने 43 दुकानों को तोड़े जाने का उदाहरण दिया और कहा कि ये सभी भाजपा समर्थक थे। आम आदमी पार्टी के बौद्ध प्रांत की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगामी "रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो" पदयात्रा की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न जिलों से आए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे।

आपदा पीड़ितों के पुनर्वास और उनकी आजीविका पर भी विशेष फोकस

देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आपदा राहत बचाव में सहयोग देने वाले कार्मिकों को सम्मानित करते हुए कहा कि आपदा केवल इमारतें या सड़कें ही नहीं तोड़ती, आपदा लोगों के आत्मविश्वास और भविष्य को भी चोट पहुंचाती हैं। इसलिए राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आपदा पीड़ितों को केवल मुआवजा ही न दिया जाए, बल्कि उनके पुनर्वास और उनकी आजीविका पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पटेल नगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।इस मौके पर मुख्यमंत्री आपदा के दौरान राहत एवं बचाव अभियान में योगदान देने पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी के कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मान ऐसे कर्मियों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने आपदा के दौरान राहत एवं बचाव अभियान में अपनी जान की परवाह किए बिना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबने 2013 की केदारनाथ आपदा की त्रासदी को देखा है, जब जय प्रलय में हजारों लोगों की जानें चले गईं थीं। इसी प्रकार 2021 में चमोली की ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटी में आई आपदा ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वर्ष 2023 में जोशीमठ का धंसाव भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आया। इस वर्ष भी उत्तरकाशी, चमोली और देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की अनेक घटनाओं का हमने सामना करना पड़ा।
इन आपदाओं में कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग लापता हुए और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कठिन परिस्थितियों में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती मानव जीवन की रक्षा करने की थी, यही समय था, जब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित पुलिस- प्रशासन के लोगों ने आपदा में घायल और मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय हमारे राहत कर्मियों ने न केवल प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, बल्कि पुनर्वास और राहत शिविरों का भी संचालन किया। सिल्क्यारा टनल में फंसे मजूदरों के लिए चलाए गए अभियान को नहीं भूल सकते। तब दिन-रात चलने वाले बचाव अभियान पर पूरे देश की निगाह थी।

फास्टैग नहीं होने पर दोगुनी पेनल्टी से मिली बड़ी राहत, यूपीआई से देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब वाहनों को फास्टैग न होने पर हो दोगुना टोल शुल्क नहीं देना होगा। अब अगर वाहन चालक का फास्टैग सक्रिय नहीं है तो वो यूपीआई से टोल दे सकता है। इस दौरान उसे 1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा। दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल शुल्क भरने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत वाहनों में फास्टैग न होने पर यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति होगी। इसके लिए उसे सवा गुनी यानी 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा। नए नियम को लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई व्यवस्था 15 नवंबर से लागू की जाएगी।

फॉस्टैग में बैलेंस नहीं होने पर देना पड़ता दोगुना शुल्क
गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नकदी से भुगतान पर फजीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। 2022 तक फास्टैग की पहुंच लगभग 98% हो चुकी है। जिसके चलते टोल बूथों पर औसत प्रतीक्षा का समय घटकर 47 सेकेंड हो गया था। वर्तमान में अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं है या फिर उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो उसके दोगुना भुगतान करना पड़ता था।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्षता में आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सभी श्रमिकों प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका अभिवादन किया

दिल्ली प्रदेश भाजपा ने श्रमिकों को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी श्रमिकों का अभिनंदन किया

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली प्रदेश के नवनिर्मित कार्यालय भवन के निर्माण में योगदान देने वाले सभी श्रमिकों के सम्मान में शनिवार को 'श्रमिक सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्षता में आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सभी श्रमिकों प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी श्रमिकों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं हम सभी भाजपा परिवार के कार्यकताओं ने इस भवन के निर्माण में अपनी तपस्या, परिश्रम और समर्पण से योगदान देने वाले श्रमिक भाइयों का सम्मान कर उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। यह वही भावना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति में एक आदर्श संस्कार के रूप में स्थापित किया है कि राष्ट्र के विकास का सच्चा श्रेय उस श्रम को है, जो तप और समर्पण से संनादित है। चाहे वह संगठन का कार्यालय हो या राष्ट्र की प्रगति का भवन, उसकी नींव में श्रमिकों का परिश्रम ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज भाजपा कार्यालय का यह भव्य और दिव्य स्वरूप हमारे श्रमिक भाइयों के तप, त्याग और अटूट समर्पण का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि परिश्रम और तपस्या के प्रति सम्मान ही हमारी राजनीति और संगठन की प्राण-धारा है। 'श्रमिक सम्मान समारोह' में दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा, सांसद कमलजीत सहरावत, भवन निर्माण समिति के सदस्य योगेंद्र चंदोलिया, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग एवं सुमन कुमार गुप्ता के साथ कार्यालय मंत्री ब्रजेश राय एव अमित गुप्ता भी उपस्थित रहे।

दिल्ली सरकार ने आर्थिक सहायता पाने वाले लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन को दी मंजूरी

नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता पाने वाले लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग छह लाख लाभार्थियों को दी जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं की आर्थिक सहायता में पारदर्शिता और दक्षता को और मजबूत करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी सहायता वास्तविक और पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने पिछले दिनों इसे मंजूरी प्रदान की थी। इस आशय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बताया कि समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार इन योजनाओं में प्रभावी पारदर्शिता चाहती है, इसके लिए लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससीएसपीवी) के साथ साझेदारी की है। यह संस्था भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित एक विशेष प्रयोजन वाहन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सत्यापन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा और उनका जीवन प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा।

'राहुल का विदेशी मंचों पर भरोसा जताना 'भारत-विरोधी संस्कारों' की निशानी'

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भारत की धरती से अधिक भरोसा विदेशी मंचों पर जताना उनके भारत-विरोधी संस्कारों को दशार्ता है। सचदेवा ने एक्स पोस्ट में राहुल गांधी के हालिया बयानों की आलोचना करते हुए लिखा कि लोकतंत्र पर भाषण देने से पहले उन्हें अपनी पार्टी का इतिहास देखना चाहिए। इमरजेंसी की याद आज भी भारत की आत्मा में जिंदा है। भारत को कमजोर बताने वाले आपके बयान हर देशवासी के आत्मसम्मान पर प्रहार हैं। सचदेवा ने कहा कि भारत आज आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर खड़ा है, लेकिन राहुल उस आत्मविश्वास को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसे राजनीतिक मतभेद से आगे बताते हुए कहा, यह विरोध नहीं, वतन से वैर है; यह राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि मानसिक दिवालियापन है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन देश की बदनामी कतई स्वीकार्य नहीं। बार-बार भारत की धरती से ज्यादा भरोसा विदेशी मंचों पर जताना आपके भारत-विरोधी संस्कारों की निशानी है। आप अब अपमान के प्रतीक बन चुके हैं।

ग्रीन पार्क: स्वच्छता के लिए अत्याधुनिक सुपर सकर और जेटिंग मशीन तैनात

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता व मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय ने शनिवार को ग्रीन पार्क क्षेत्र में जल बोर्ड की सुपर सकर और जेटिंग मशीन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक मशीनें अब क्षेत्र में सीवर सफाई, जल निकासी और स्वच्छता को और तेज एवं प्रभावी बनाएंगी। विधायक सतीश उपाध्याय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली को और स्वच्छ, आधुनिक और स्वस्थ बनाने की दिशा में यह एक ठोस कदम है।

मुख्यमंत्री ने पल्ला गांव से हाथी घाट तक विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया

नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बोट से यमुना नदी के प्रवेश बिंदु पल्ला गांव से लेकर आईटीओ के नजदीक स्थित हाथी घाट तक विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और कपिल मिश्रा के अलावा लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना तट पर महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर सरकार पूरी गंभीरता और युद्धस्तर पर काम में जुटी है। आज पल्ला गांव से लेकर हाथी घाट तक लगभग तीन घंटे तक विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और बोट से यमुना जी के किनारों का विस्तृत सर्वे किया। उन्होंने कहा कि यह जमीनी सर्वेक्षण केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा नहीं, बल्कि दिल्ली में एक भव्य और सुव्यवस्थित छठ आयोजन सुनिश्चित करने की ठोस नींव है।

यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भाइयों-बहनों को दिल्ली की मिट्टी से जोड़ता है और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करता है। संबंधित विभागों को साफ-सफाई, घाटों के निर्माण, सुरक्षा और अन्य सभी सुविधाओं की रूपरेखा शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लाखों श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के छठ मईया की पूजा-अर्चना कर सकें। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने छठ को यमुना से दूर कर दिया था। यमुना किनारे इस बार आस्था के महापर्व छठ का भव्य आयोजन होगा। उनकी सरकार पल्ला गांव से लेकर ओखला तक छठ के आयोजन की तैयारियों में पूरी निष्ठा और तत्परता से जुटी है। जब यमुना के घाटों पर लाखों श्रद्धालु डूबते सूरज और उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे तब वह क्षण हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय बने, यही हमारा संकल्प और प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में पूर्वांचलवासियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए उनकी धार्मिक आस्था व सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में यमुना के प्रवेश स्थल पल्ला से लेकर अंतिम स्थल ओखला तक दोनों किनारों पर छठ पर्व का आयोजन किया जाएगा।

इन दोनों किनारों पर जहां भी छठ पर्व के लिए समतल किनारे उपलब्ध होंगे, वहां सरकार की ओर से व्रतधरियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

हिंदू-देवताओं को गाली देते हुए बनाया वीडियो, वायरल होने के बाद युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली

दिल्ली के वसंतकुंज साउथ इलाके में एक शख्स ने हिंदू देवी-देवाताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बनाया। यह वीडियो शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर जमकर हंगामा हुआ और विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य हिंदू संगठनों के लोग वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स पर कार्रवाई की मांग करने लगे। लोग युवक की पहचान कर उसके घर के बाहर जमा होकर विरोध-प्रदर्शन करने लगे। मामले की सूचना के बाद वसंतकुंज साउथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों के बयान पर पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर आरोपित युवक मोहम्मद शमशाद आलम को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक मोहम्मद शमशाद आलम से पूछताछ कर रही थी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उसने वीडियो कब और क्यों बनाया था। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि 4 अक्टूबर को वसंतकुंज साउथ थाना पुलिस को सूचना मिली एक शख्स ने हिंदू देवी-देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाई है। वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग उसके घर के बाहर विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जहां विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, रूबी नर्सरी पर जमा थे।

विक्की टक्कर गैंग के दो शातिर बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली

द्वारका जिले की एएटीएस टीम ने कुख्यात विक्की टक्कर गैंग के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक देशी पिस्टल और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान शिवम उर्फ भाटी (23) और नन्हे (22) के रूप में हुई है। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने शनिवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि विक्की टक्कर गैंग का सक्रिय सदस्य शिवम अपने साथी के साथ द्वारका नॉर्थ इलाके में अवैध हथियार लेकर घूम रहा है और वारदात को अंजाम दे सकता है। सूचना पर पुलिस टीम ने गंदा नाला सर्विस रोड, नजफगढ़ पर घेराबंदी की। जैसे ही दोनों आरोपित बाइक पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आरोपितों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा कर पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। तलाशी में शिवम के पास से देशी पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद हुई, जो जनकपुरी इलाके से चोरी हुई थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि शिवम को 2020 में गैंग में शामिल किया गया था। उसने गैंग शूटर अमन बावानिया के इशारे पर अवैध वसूली के लिए फायरिंग की थी। 2021 में उसने साथियों के साथ सांसी समुदाय के एक घर पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। शिवम पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास और हथियारबंदी शामिल है। वहीं नन्हे 24 मामलों में पहले ही शामिल रह चुका है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई गैंगस्टरों और हथियारबंद अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

जाफराबाद में लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, चार दबोचे

नई दिल्ली

उत्तर-पूर्वी जिले के जाफराबाद इलाके में हुई लूट की वारदात में पुलिस ने दो नाबालिग समेत चार आरोपितों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान चौहान बंगर निवासी हारिश (19), चौहान बंगर निवासी सुहैल उर्फ भूरा (21) व दो नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, तीन अक्टूबर की शाम करीब 6:21 बजे गली नंबर-10, चौहान बंगर स्थित एक मनी ट्रांसफर की दुकान पर तीन नकाबपोश बदमाश घुस आए।

उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगा-रोधी मॉक ड्रिल

नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह उत्तरी-पूर्वी जिले में दंगा-रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास बेला फार्म, यमुना खादर, शास्त्री पार्क में किया गया। जिसका उद्देश्य बल की संचालन क्षमता और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की तैयारी को जांचना था।

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ड्रिल की शुरूआत सुबह आठ बजे की गई। इसमें कुल 170 पुलिसकर्मी शामिल हुए। जिनमें एक एसीपी, सात इंस्पेक्टर और 162 अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान वाटर कैनन, वज्र, विक्रांत और एम्बुलेंस की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों की गैस गन और ए.आर.ई. उपकरण चलाने की दक्षता की भी जांच की गई। वहीं पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया ऐसे अभ्यास समय-समय

ड्रग्स तस्करी के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ यूनिट ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से डेढ़ किलो से अधिक हेरोइन बरामद की गई है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कई करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि जहांगीरपुरी का रहने वाला इंजमाम-उल-हक ड्रग्स की डिलीवरी करने वाला है। सूचना को पुख्ता कर टीम ने स्वरूप नगर एक्सटेंशन और भलस्वा डेयरी के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। उसके पास से 1259 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि इंजमाम जहांगीरपुरी निवासी बाबू खान के साथ मिलकर ड्रग्स की तस्करी करता था। बाबू खान पहले भी हत्या के प्रयास, अवैध शराब तस्करी और लूट जैसे कई गंभीर मामलों में जेल जा चुका है और हाल ही में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में जमानत पर बाहर आया था। इंजमाम की गिरफ्तारी के बाद बाबू खान फरार हो गया था।

, लेकिन पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर उसे भी दबोच लिया।

ओडिया समाज ट्रस्ट के कार्यालय से 25 लाख की चोरी के मामले में दो गिरफ्तार

नई दिल्ली

दक्षिण पश्चिम जिले के सरोजनी नगर थाना पुलिस ने ओडिया समाज ट्रस्ट के कार्यालय से 25 लाख की चोरी के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने अपराध सीरीज क्राइम पेट्रोल देखकर पहले भेष बदला और फिर आरके पुरम स्थित ओडिया समाज ट्रस्ट के कार्यालय से 25 लाख रुपये पर हाथ साफ किया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान राजेन्द्र कुमार और राजेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 23.50 लाख रुपये और कार्यालय की अलमारी काटने में इस्तेमाल की गई एक कटर मशीन बरामद की गई है। दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने शनिवार को बताया कि 23 सितंबर को ओडिया समाज ट्रस्ट के कार्यालय में चोरी होने की सूचना मिली। एएसआई नरेंद्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां ओडिया समाज ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक एसएमएस दास की बेटी जेआर दास मौके पर मिली। एसएचओ अतुल त्यागी की टीम ने उनके बयान पर संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने 11 दिनों में 40 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की, मौके पर मौजूद संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी निगरानी का विश्लेषण किया और कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के दौरान टीम ने एनजीओ कार्यालय में प्रवेश करते और बाद में ऑटो-रिक्शा में निकलते समय भेष बदलते (टोपी, गर्दन पर तौलिया और दस्ताने पहने) दो संदिग्धों की पहचान की। पुलिस टीम ऑटो के नम्बर की मदद से चालक तक जा पहुंची। चालक ने बताया कि उसने दोनों संदिग्धों को नेताजी नगर में छोड़ा था। पुलिस टीम ने नेताजी नगर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया तो एक आरोपित राजेन्द्र कुमार की पहचान की गई। पुलिस ने गोल चंबारी के पास राजेन्द्र कुमार को दबोच लिया। राजेन्द्र ने सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म कबूल कर लिया। जिसके बाद उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की रकम बरामद कर ली गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि वारदात का मुख्य आरोपित राजेन्द्र

खजूरी चौक से लापता दो वर्षीय मासूम का शव बरामद, जांच जारी

नई दिल्ली

उत्तर पूर्वी जिले के खजूरी चौक इलाके से लापता हुए दो साल का बच्चा शनिवार को संदिग्ध हालात में मृत मिला। पुलिस के अनुसार तीन अक्टूबर को बच्चे की गुमशुदगी की सूचना थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस टीम ने रात भर बच्चे की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस अधिकारी के अनुसार शनिवार सुबह पुलिस ने दोबारा तलाशी अभियान शुरू किया। दोपहर के समय पुलिस को बच्चे का शव सीआरपीएफ कैंप की बाउंड्री वॉल के पास जंगल से बरामद हुआ। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और सबूत जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि बच्चे की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा।

वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो पूरे मामले की जांच कर रही है।

संपादकीय

राजस्थान बन रहा है परमाणु बिजलीघर का हब

ऊर्जा की आवश्यकता किसी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रगति के लिए आधारभूत होती है। भारत जैसे विशाल और जनसंख्या में विश्व में दूसरे नंबर पर ऐसे देश के लिए, ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ती है। यह मांग न सिर्फ बिजली उत्पादन की है बल्कि उसका विश्वसनीय, सफल, स्वच्छ और सतत स्रोत चाहिए। ऐसी स्थिति में परमाणु ऊर्जा विकल्पों में उभरती है। राजस्थान राज्य, जहाँ जल-वायु की चरम स्थितियाँ, विशाल क्षेत्रफल और प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु बिजलीघर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

राजस्थान का पहला वाणिज्यिक परमाणु बिजली घर रावतभाटा में स्थित है, जिसे राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना (आरकेपीपी) के नाम से जाना जाता है। यह परियोजना न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है। आरकेपीपी यूनिट की स्थापना भारत में पहला परमाणु बिजलीघर होने के कारण महत्वपूर्ण है। इसका पहला वाणिज्यिक संचालन 1970 के दशक में शुरू हुआ था। बाद में कई यूनिटें स्थापित की गईं, विस्तारित समय और तकनीकी उन्नयन के बाद, यूनिटों की क्षमता बढ़ी है। आरएपीपी-7 यूनिट हाल ही में ग्रिड से जुड़ा है। आरएपीपी-8 यूनिट निमार्णाधीन है।

कुल मिलाकर, इस बिजलीघर की स्थापित क्षमता बढ़ाने की लगातार प्रक्रिया जारी है ताकि बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय हो सके।

राजस्थान में ऊर्जा भविष्य की दृष्टि से सबसे बड़ी और समकालीन प्रस्तावित परमाणु परियोजना दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बैकवाटर के पास प्रस्तावित है। माही नदी के किनारे, माही बजाज सागर बाँध के उपर पानी के अथाह स्त्रोत के रूप में इस परियोजना को देखा गया है। इसमें चार इकाइयाँ प्रस्तावित है। इसकी कुल क्षमता 2,800 मेगावाट है। इसकी पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और साइटिंग क्लियंस आदि स्वीकृतियां मिल चुकी हैं तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 सितम्बर को इसका शिलायन्स होना प्रस्तावित है। इसकी पहली इकाई 2031 तक चालू हो सकती है। बाकी यूनिटें क्रमबद्ध तरीके से आयेगी। पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग ?42,000 से ?50,000 करोड़ के मध्य आंकी जा रही है।

राजस्थान में परमाणु बिजलीघर होने के कई लाभ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक स्थिर स्त्रोत है, विशेषकर जब सौर और पवन ऊर्जा मौसमी और परिवर्तनीय होती है। इससे ऊर्जा सुरक्षा और भरोसा मिलेगा। परमाणु बिजली घर स्वच्छ ऊर्जा का स्त्रोत है तथा इससे कार्बनडाइड का उत्सर्जन बहुत कम होता हैं। जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में ये महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

यह परियोजना आर्थिक विकास एवं रोजगार निर्माण में सहयोगी साबित होगी, इसके संचालन, रख-रखाव, आपूर्ति श्रृंखला आदि में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा। विशेषकर बांसवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में अवसंरचनात्मक का विकास भी होगा।प्रौद्योगिकी एवं आत्म-निर्भरता से विदेशी निर्भरता कम होगी। साथ ही देश और राजस्थान की मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे शहरों, उद्योगों और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की समस्या कम होगी।

परमाणु बिजलीघर से जुड़े कई लाभ हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साइट चयन, भूमि अधिग्रहण और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव जैसे वन क्षेत्र, नदियों, जीव-जंतु आदि को ध्यान में रखना होगा। रेडियोधर्मी उत्सर्जन की संभावना, परमाणु आपदाएँ और असाधारण हालातों जैसे भूकंप, बाढ़ आदि की तैयारी आवश्यक है।उपयोग के बाद की ईंधन सामग्री आदि का सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन लंबी अवधि की जिम्मेदारी है।परियोजनाएँ महँगी होती हैं और उन्हें पूरा करने में वर्षों लग सकते हैं। लागत बढ़ने की संभावना और समय-सीमा में देरी हो सकती है।स्थानीय लोगों में विस्थापन की आशंका, पर्यावरणीय व स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में भय और विरोध हो सकते हैं।

लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है सीईसी पर विपक्ष का महाभियोग लाने की तैयारी

अजेश कुमार

भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। यह केवल आकार या मतदाताओं की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के कारण ऐसा माना जाता है। चुनाव आयोग इस लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। वही संस्था, जो यह सुनिश्चित करती है कि हर पांच साल पर या जब भी चुनाव हों, वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हों। मगर, जब इसी संस्था की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगें, तो यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

आज भारत में यही स्थिति उभरती दिख रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। यह कदम सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद और संस्थागत निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर देश के सर्वोच्च चुनाव अधिकारी पर विपक्ष इतना आक्रामक क्यों है? क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है, या सचमुच चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदिग्ध हो चुकी है? और सबसे अहम सवाल, क्या भारत की संवैधानिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि ऐसे विवादों से लोकतंत्र की बुनियाद हिलने से बचाई जा सके?

विपक्षी दलों का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार अपनी भूमिका में निष्पक्ष नहीं दिख रहे। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का आरोप है कि हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ने एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी की तरह नहीं, बल्कि बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात की। यह आरोप साधारण बयानबाजी नहीं है, क्योंकि यह सीधे-सीधे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रहार करता है। विपक्ष का कहना है कि जब राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने मतदाता सूची में धांधली, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), महाराष्ट्र व हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जैसे गंभीर मुद्दे उठाए, तो सीईसी ने ठोस जवाब देने की बजाय मजाक उड़ाया और तंज कसा।

दूसरी तरफ, ज्ञानेश कुमार का बचाव है कि ये सारे आरोप निराधार और राजनीतिक हैं। उनका कहना है कि अगर वाकई वोट चोरी जैसी कोई संगीन बात है, तो विपक्ष को शपथपत्र देकर औपचारिक रूप से आरोप सिद्ध करना चाहिए। वरना यह केवल चुनावी प्रणाली और लाखों ईमानदार चुनावकर्मियों की छवि धूमिल करने की कोशिश है। यहां सवाल सिर्फ व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की विश्वसनीयता का है, क्योंकि यदि मतदाता ही यह मानने लगें कि चुनाव आयोग पक्षपाती है, तो मतदान की वैधता पर गंभीर संदेह खड़ा हो जाएगा। विवाद का मूल बीज राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रस्तुति से जुड़ा है। उन्होंने करीब एक घंटे तक विभिन्न उदाहरण पेश किए और दावा किया कि मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। उनका आरोप है कि यह तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि विपक्षी मतदाताओं को सूची से हटाने की सुनियोजित रणनीति है। उन्होंने बिहार में चल रहे एसआईआर को भी वोट काटने की साजिश करार दिया। तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उछालते हुए कहा कि बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्दबाजी और मनमानी से की जा रही है।

राहुल गांधी के लिए दिल्ली जीतना बड़ी चुनौती

मनोज कुमार मिश्र

कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले राहुल गांधी ने पूरा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव के साथ दौरा करने के बाद अपने लोगों में यह जताने के प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार जीत लिया है। वे और उनके समर्थक खुलेयाम आरोप लगा रहे हैं कि देश का चुनाव आयोग केन्द्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के दबाव में मतदाता और मतदान में हेराफेरी कर रहा है। चुनाव आयोग की लगातार सफाई के बावजूद विपक्ष अब वोटिंग मशीन(ईवीएम) में गड़बड़ी के बजाए सीधे वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव दो महीने बाद होने वाले हैं। यह तय सा हो गया है कि इस बार भी बिहार का चुनाव राजद और कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन और भाजपा, जनता दल(एकी) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) के बीच मुख्य रूप से होने वाला है। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से अब तक बिहार में करीब चालीस साल शासन किया है, उसके नेता बड़े ही गर्व के साथ एक तरह से राजद के पिछलग्गु बनना स्वीकार लिया है। देश में राजग, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पराजित करने का सपना देखने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली समेत उन राज्यों में भी पार्टी को नहीं खड़ी कर पा रहे हैं, जहां सालों कांग्रेस शासन में रही है। वास्तविकता तो यह है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जिस राज्य में कांग्रेस पराजित हुई है, वहां उसकी वापसी ही वहीं हो पाई है। 2024 के लोक सभा चुनाव में भाजपा पर बेबुनियाद संविधान बदलने का आरोप को कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। उससे कुछ भ्रम बना लेकिन लगातार तीसरी बार राजग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केन्द्र में सरकार बनाने में कामयाब हुई और राजग का दायरा बढ़ता ही गया।

उसके बाद हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक सभा से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी(आप) से सीटों का तालमेल था। सात में से तीन सीट कांग्रेस और चार आप लड़ी। चुनाव में सभी सातों सीटें भाजपा लगातार तीसरी बार जीती। कांग्रेस को 18.50 फीसद वोट मिले। माना जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थक वोट पर दिल्ली में राज कर रही आप को लग रहा है कि उसके साथ तालमेल करने से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और देर-सबेरे आप को ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए उसने विधानसभा चुनाव अकेले चुनाव लड़ना तय किया। चुनाव में भाजपा को जीत मिली और 27 साल दिल्ली की सत्ता में उसकी वापसी हुई। दस साल से दिल्ली में सरकार चला रही आप को उससे केवल दो फीसद वोट कम मिले लेकिन सीटों का फासला काफी रहा। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा 45.86 वोट के साथ 48 और आप को 43.57 फीसद वोट के साथ 22 सीट जीत पाई। कांग्रेस को करीब छह फीसद वोट मिले। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस के नेता प्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि आप के पराजय के साथ कांग्रेस की वापसी होगी लेकिन अभी तक एक भी कार्यक्रम ऐसा न हुआ जिससे लगे कि कांग्रेस दिल्ली में वापसी के लिए कोई प्रयास कर रही है। न ही आप में कोई भगदड़ मची।

2006 के परिसीमन में पूर्वी दिल्ली सीट दो हिस्सों में (पूर्वी दिल्ली और दिल्ली उत्तर पूर्व) बंटी। उससे पहले पूर्वी दिल्ली सीट से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित सांसद थे जो परिसीमन के बाद 2009 में उसकी एक सीट से सांसद बने और 2014 में पराजित हुए। 2019 में पूर्वी दिल्ली की दूसरी सीट दिल्ली उत्तर पूर्व से उनकी मां और दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित चुनाव लड़ी और पराजित हुई। शीला दीक्षित 2019 में आप से समझौता का विरोध किया तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के साथ जबरन लोक सभा चुनाव लड़वाया गया। सत्ता सुख भोगने की आदत पड़ जाने के चलते एक ही चुनाव की हार ने कांग्रेस को संकट में ही ला दिया।

अपनी चिंता में लगे नेताओं ने पार्टी को हाशिए पर ला दिया। 2013 विधानसभा चुनाव की हार के बाद पार्टी बिखरती ही गई। 2015 के चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंद सिंह लवली और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया अजय माकन को। इससे नाराज लवली ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने अजय माकन 2019 के लोक सभा चुनाव में आप से तालमेल की मुहीम चलाई। बताया गया कि कांग्रेस का एक वर्ग को सात में से दो सीट पर भी समझौता करने को तैयार हो गया था। जिस पार्टी ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाया उससे समझौता करने का शीला दीक्षित के भारी विरोध किया। समझौता न होने पर भारी मन से अजय माकन नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़कर हारे। वे भी बिना प्रदेश अध्यक्ष तय हुए बीमारी के बहाने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी।

त्रासदी यह है कि वही अजय माकन आज की तारीख में राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। उन्हें लोक सभा चुनाव हारने के बाद पहले हरियाणा से और वहां से पराजित होने के बाद कर्नाटक से राज्य सभा का सदस्य बनाया गया। वे पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और बिहार चुनाव के सुपर प्रभारी। 2013 विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का दिल्ली में प्रयोग ही चल रहा है।2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली और कांग्रेस का वोट औसत घटकर 4.26 हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में शीला दीक्षित के निधन के बाद चौधरी अनिल कुमार प्रदेश अध्यक्ष बने। लवली थोड़े ही समय भाजपा में रहकर कांग्रेस में लौट आए और 2019 का लोक सभा चुनाव पूर्वी दिल्ली सीट से मजबूती से लड़े। उन्हें 2023 में अनिल कुमार के इस्तीफा देने पर दोबारा अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन 2024 के लोक सभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे में अपनी भूमिका न होने से नाराज होकर उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ लिया। अब विधायक बनने के बाद भाजपा ने उन्हें यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। उसी दौरान बड़ी तादात में कांग्रेस के अनेक नेता भाजपा में शामिल हुए। अब आर्थिक रूप से संपन्न पूर्व विधायक देवेन्द्र यादव दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष हैं।

दिल्ली में कांग्रेस वहीं पहुंच गई जहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा मजबूत तीसरे दल वाले राज्य में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अगुवाई में भाजपा ने तो गुजरात, मध्यप्रदेश में कांग्रेस को सालों से सत्ता से बेदखल कर दिया है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड उत्तराखंड, बिहार और पंजाब इत्यादि में तो उसकी सत्ता में वापसी संभव ही नहीं लग रही है। हर राज्य में कांग्रेस उनकी कृपा से कुछ सीटें पा जाती है। देश में भाजपा की विकल्प बनने का सपना देख रही कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अलावा शायद ही किसी राज्य में अपने बूते सरकार बना पाएगी इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है। राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के भी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस के इस कदर बूरे दिन आ गए हैं कि वह उन दलों के साथ उनसे कम सीटों पर चुनाव लड़कर अपने को धन्य मान रही है. जिनके वजूद ने उसे हाशिए पर पहुंचा दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस इन्हीं क्षेत्रीय दलों के बूते भाजपा के मुकाबले बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है और उनके ही बूते देश पर राज करने का सपना देख रही है।

पहले ईवीएम(ईलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन) के खिलाफ कांग्रेस काफी समय से ने अभियान चला रही है। जबकि ईवीएम से चुनाव कांग्रेस राज में ही शुरू हुआ था। इतना ही नहीं जब कांग्रेस किसी राज्य में जीतती है तब ईवीएम पर कुछ नहीं बोलती। केवल हारने पर ईवीएम मुद्दा होता है। अब चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर वोट चोरी का मनगढ़ंत आरोप लगाकर केन्द्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का जबरन प्रयास कर रही है। यह उसी तरह से उठाया जा रहा है जैसे लोक सभा चुनाव में संविधान खतरे में की झूठा प्रचार किया जा रहा था। बताया जा रहा थी इसे ही मुद्दा बनाकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्षी नेताओं ने बिहार चुनाव को प्रयोगशाला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह सफल हुआ तो बाकी राज्यों में भी इसे मुद्दा बनाएंगे। अति उत्साह में उनसे गलती हो गई। बिहार के दरभंगा में विपक्षी मंच से प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द बोले गए। इसे प्रधानमंत्री और राजग के नेताओं ने उसी तरह मुद्दा बना लिया जिस तरह से 2019 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नीच कहना बन गया था।

आईसीसी से जुड़ा भारत इसलिए पाक से निभाता है क्रिकेट रिश्ते

अजय कुमार

अभी कुछ दिनों पूर्व दुबई में खेले गए एशिया क्रिकेट कप के एक मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद दिया था। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ था, ज्यादातर मौकों पर भारत अपने दुश्मन देश को जंग के मैदान से क्रिकेट के मैदान तक में पटकनी देता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार उस समय हॉकी से लेकर क्रिकेट तक के अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले होते रहे थे, जब दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव या जंग जैसे हालात रहे थे। पूर्व में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर आज मोदी की सरकार, कोई इन अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से किनारा नहीं कर सकती है। यह बात सब जानते और समझते हैं, लेकिन कुछ कथित बुद्धिजीवी और विपक्ष के नेता एशिया कप में भारत-पाक के बीच के मुकाबले ही आड़ लेकर मोदी सरकार को देश विरोधी साबित करने में लगे हैं। इसके लिए जनता को भड़काया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए बाध्य था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय टूनार्मेंटों में भाग लेना किसी भी क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी और समझौते का हिस्सा है। यदि भारत खेलने से इंकार करता तो कई स्तरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, जिसमें आर्थिक, राजनैतिक

और खेल जगत की प्रतिष्ठा प्रभावित होती। इस मुद्दे पर भारत में विरोध मुख्यतः राजनीतिक है, पर इसके पीछे आर्थिक, कूटनीतिक और खेल प्रबंधन की मजबूरियां भी हैं।

एशिया कप जैसा टूनार्मेंट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) द्वारा आयोजित होता है, जिसमें सदस्य देशों को अपनी टीम भेजनी पड़ती है और पूरे मैच शेड्यूल का पालन करना होता है। अगर भारत भाग नहीं लेता या पाकिस्तान के साथ खेलने से इंकार करता, तो भारत को टूनार्मेंट से बाहर कर दिया जाता और भविष्य के आईसीसी इवेंट्स में भारत की भागीदारी पर सवाल उठते। वहीं आर्थिक दृष्टि से, भारत-पाक मैच सबसे अधिक आकर्षण पैदा करता है, जिससे ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और रेवेन्यू में भारी नुकसान होता। भारत की छवि वैश्विक क्रिकेट जगत में नकारात्मक होती और आईसीसी सख्त कदम उठाता, जैसे जुमार्ना या बैन।

यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत-पाक मैच सबसे बड़े दर्शक संख्या, हाईएस्ट टीवी रेटिंग्स और स्पॉन्सरशिप डील्स का केंद्र है। भारत के न खेलने से आईसीसी और एसीसी को करोड़ों रुपये का नुकसान होता। आईसीसी में भारत की वित्तीय हिस्सेदारी घट जाती। अन्य टेलीविजन नेटवर्क और ब्रॉडकास्टर्स को री-नेगोशिएशन करनी पड़ती। दरअसल, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि खेल प्रतियोगिताओं को लेकर भारत का रुख साफ है। पाकिस्तान से द्विपक्षीय मैच नहीं, पर बहुपक्षीय टूनार्मेंट्स में सरकार की अनुमति से खेलना ही पॉलिसी है। द्विपक्षीय सीरीज या पाक में टूनार्मेंट की बीजेपी/सरकार इजाजत नहीं देती, पर एशिया कप, वर्ल्ड कप जैसे टाइटल्स में भाग लेना जरूरी है, ताकि भारत की क्रिकेट रणनीति, रेपुटेशन और ग्लोबल पोजिशन सुरक्षित रहे।

बहरहाल, भारत में इस मैच को लेकर भारी विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक बयानबाजी की लहर देखी गई। प्रमुख विपक्षी दलों से लेकर राजनीतिक संगठनों आम आदमी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस आदि विरोध में सड़क पर उतर आए। पाक क्रिकेटर्स के पुतले जलाए गए। सुप्रीम कोर्ट तक याचिका गई, कि राष्ट्रहित से ऊपर नहीं है क्रिकेट। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में सीमा पार आतंकी घटनाओं के बाद आम भारतीय जनमानस में पाकिस्तान के खिलाफ मैच ही विरोध का प्रतीक बन गया है। स्पोर्ट्स को भावनात्मक तौर पर देखा जाता है। परिवारों, फौजी समुदाय और युवा वर्ग में मैच बहिष्कार की आवाज तेज हो जाती है। यही वजह है कि ह्वराष्ट्रभक्ति बनाम रुपयाह्व की बहस अब तक जारी है, जबकि केंद्र सरकार और बीसीसीआई बहुपक्षीय टूनार्मेंट्स में राजनीतिक दिशा-निर्देश का पालन करते हुए खेलने को मजबूर हैं। वहीं द्विपक्षीय खेल मुकाबलों में खेल अधिनियम के तहत बीसीसीआई और खेल मंत्रालय का तालमेल जरूरी है।

कुल मिलाकर भारत-पाक क्रिकेट विवाद राजनीति की रणभूमि बन चुका है, पर ह्वखेलह्व की मजबूरी ऐसी है कि भारत आईसीसी या एसीसी के सामने पूरी तरह से मैच से पीछे नहीं हट सकता। भारत का न खेलना खिलाड़ियों के करियर, निवेश, और अगले वर्ल्ड इवेंट्स पर असर डालता। विरोध राजनीतिक है, पर पर्दे के पीछे खेल एवं आर्थिक हित ज्यादा ताकतवर हैं। इस मैच का विरोध भारत में कूटनीतिक और भावनात्मक स्तर पर है, लेकिन भारत को खेलने की मजबूरी उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता, वित्तीय निवेश और खेल प्रबंधन के कारण है। यदि भारत इनकार कर देता, तो भारी वित्तीय नुकसान, अंतरराष्ट्रीय सजा और भारत की क्रिकेट प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते।

योगी राज में दूरी और असुरक्षा से सहमी महिला

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की तबादला नीति और उससे जुड़ी जटिलताओं पर लंबे समय से बहस जारी रही थी। सरकार द्वारा बार-बार नए आदेश जारी किए जा रहे थे, किन्तु शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पा रहा था। विशेषकर महिला शिक्षिकाओं के लिए यह मुद्दा किसी बोझ से कम नहीं माना जा रहा था। दूरस्थ स्थानों पर नियुक्ति, परिवार से दूरी, परिवहन की कठिनाइयाँ और कार्यस्थल पर अपेक्षित सुविधाओं का अभाव उनके जीवन को और कठिन बना देता था।राज्य में यह कहा जा रहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यालयों में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिए तबादला नीति बनाई गई थी। परंतु जब उसका क्रियान्वयन हुआ तो उसमें पारदर्शिता की कमी और पक्षपात के आरोप लगे। जिन शिक्षकों को पास में नियुक्ति की अपेक्षा थी, वे कई बार सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक यह कहा करते थे कि विद्यालयों तक पहुँचना स्वयं एक बड़ी चुनौती थी। सड़कें जर्जर रहती थीं और परिवहन के साधन सीमित होते थे।

महिलाओं के लिए यह कठिनाई और बढ़ जाती थी। विवाहित महिला शिक्षिकाएँ परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाने में असमर्थ हो रही थीं। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच यदि किसी दूरस्थ गाँव में नियुक्ति हो जाती थी, तो दैनिक जीवन कष्टमय हो जाता था। कई बार यह सुनने में आता था कि महिला शिक्षिकाएँ सुरक्षा कारणों से अकेले विद्यालय तक जाने में आशंकित रहती थीं। अनेक महिला शिक्षिकाएँ यह अनुभव कर रही थीं कि यदि विद्यालय तक जाने के लिए बस या साझा सवारी उपलब्ध न हो, तो सुबह-सुबह घर से निकलकर शाम को अंधेरा होने के बाद लौटना बहुत असुरक्षित लगता था। कुछ प्रकरणों में यह बताया जा रहा था कि अभिभावक और परिवारजन स्वयं

महिलाओं को रोजाना विद्यालय तक पहुँचाने और वापस लाने के लिए बाध्य हो रहे थे। यह बोझ पूरे परिवार के जीवन को प्रभावित करता था।

जब शासन की ओर से यह घोषणा की गई थी कि तबादला नीति के माध्यम से शिक्षकों को उनकी प्राथमिकता दी जाएगी, तब शिक्षकों ने उम्मीद जताई थी। किन्तु वास्तविकता में यह देखा गया कि कई नाम आवेदन करने के बावजूद अपेक्षित रह गए। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कुछ शिक्षिकाएँ यह कह रही थी कि उनकी वरिष्ठता और सेवा अवधि को अनदेखा किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों और पिछड़े गाँवों में नियुक्त महिला शिक्षिकाओं का दर्द और गहरा था। वे यह मान रही थीं कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि वहाँ तक सुरक्षित पहुँचना किसी संघर्ष से कम नहीं होता।

समाज में शिक्षकों को आदर्श माना जाता रहा है, परंतु जब स्वयं उनका जीवन संघर्षमय हो तो यह आदर्श धुंधला पड़ने लगता है। महिला शिक्षिकाओं ने अपने अनुभव साझा किए थे कि सुबह-सुबह परिवार को छोड़कर अजनबी परिवेश में जाना, छोटे-छोटे बच्चों से दूर रहना और लगातार असुरक्षा झेलना उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर थका देता था। कई शिक्षिकाओं ने यह कहा था कि परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाएँ तो छुट्टी लेकर घर पहुँचना आसान नहीं होता। लंबी दूरी और सीमित परिवहन सुविधा इस समस्या को और विकट बना देती थी। कहा जाता है पढ़ाई का वातावरण तब ही बेहतर बन सकता था जब शिक्षक मानसिक रूप से संतुलित और संतुष्ट हों। किंतु जब शिक्षकों को स्थानांतरण की अनिश्चितता और दूरदराज की कठिन नियुक्तियों का बोझ झेलना पड़ता, तो उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती थी।

बच्चों को पूर्ण मनोयोग से पढ़ाना कठिन हो जाता था। महिला शिक्षिकाओं ने यह स्वीकार किया था कि कई बार वे पढ़ाते समय भी मन ही मन घर और बच्चों की चिंता करती थीं। इस कारण उनकी अध्यापन की जो क्षमता होती थी, उसमें कमी आ जाती थी।

शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं की ओर से यह मांग लगातार उठती रही थी कि नीति में पारदर्शिता लाई जाए। वरिष्ठता, सेवा अवधि और पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्थानांतरण किया जाए। विशेषकर महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा, बच्चों की देखभाल और परिवार से निकटता को प्राथमिकता दी जाए।

कई संगठनों ने यह प्रस्ताव रखा था कि विवाहित महिला शिक्षिकाओं को संभव हो सके तो पति के कार्यस्थल के निकट ही नियुक्ति दी जाए। अविवाहित और युवा शिक्षिकाओं को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन वाले क्षेत्रों में रखा जाए। अतिरिक्त आवश्यकता के बिना किसी को अत्यधिक दूर न भेजा जाए।

PoK में प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी सरकार, आंदोलन खत्म करने का ऐलान

एजेंसी

पाकिस्तान। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (**PoK**) में कई दिनों से जारी जन आंदोलन थम गया है. पीओके सरकार और अवामी एक्शन कमेटी (AAC) के बीच हुए समझौते में सरकार ने 38 में से 21 मांगें मान ली हैं. इसके बाद अवामी एक्शन कमेटी ने सभी विरोध-प्रदर्शन समाप्त करने का ऐलान किया है. हालांकि, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की याद में अगले तीन दिनों तक शोक जुलूस निकाले जाएंगे.

समझौते के तहत विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुआवजा मिलेगा और उनके एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी दी जाएगी. घायलों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. हिंसा और मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसकी न्यायिक जांच भी कराई जाएगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले लिए हैं. पीओके में दो नए बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, बनाए जाएंगे और सभी मौजूदा बोर्डों को 30 दिनों में पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन लगाई जाएगी. इसके अलावा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए 15 दिनों में फंड जारी किए जाएंगे.

बिजली और विकास योजनाएं

पीओके की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए पाकिस्तान सरकार 10 करोड़ रुपये जारी करेगी. मीरपुर जिले में विस्थापित परिवारों को 30 दिनों में जमीन दी जाएगी. गुलपुर और रहमान (कोटली) में पुल बनाए जाएंगे और डाडियाल क्षेत्र में जलापूर्ति व ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी.

अन्य फैसले

सरकार ने मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या घटाकर अधिकतम 20 करने का फैसला लिया है. मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने की योजना पर जल्द घोषणा होगी. संपत्ति हस्तांतरण कर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दरों के समान किया जाएगा. 2019 के हाई कोर्ट के जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े फैसले को लागू किया जाएगा. 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा. वहीं, 1300 सीसी वाहनों से जुड़ी परिवहन नीति की समीक्षा भी की जाएगी.

10 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है गद्दाफी का बेटा, लीबिया में होगा बड़ा उलटफेर?

एजेंसी

लीबियाई. हैन्निबल गद्दाफी, पूर्व लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी का बेटा है. मुअम्मर गद्दाफी ने 27 साल की उम्र में लीबिया में तख्तापलट किया था. 42 सालों तक देश में राज किया. अब तानाशाह का बेटा जेल से बाहर आ सकता है. हैन्निबल गद्दाफी दिसंबर 2015 से लेबनान में हिरासत में है. उस पर 1978 में इमाम मूसा सद्र, शेख, हसन याकूब और पत्रकार अब्बास बद्रद्दीन के अपहरण और लापता होने में जानकारी छिपाने का आरोप है. हालांकि, हैन्निबल दावा करता रहा है कि उसे अपहरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

हैन्निबल गद्दाफी के फ्रांसीसी वकील लौरेंट बायोन के अनुसार, पत्रकार अब्बास बद्रद्दीन के बेटे जहीर बद्रद्दीन के परिवार ने हैन्निबल की रिहाई का समर्थन किया है और 1 अक्टूबर को इस संबंध में नोटिस पर हस्ताक्षर किए. यह अनुरोध लेबनानी महाप्रॉक्यूटर जनरल को भेजा गया है, जिन्हें 24 घंटे के अंदर अपनी राय देनी होगी.

10 साल से जेल में बंद

हैन्निबल पिछले 10 साल से बेरूत में जेल में बंद है और अब तक उसे सिर्फ एक बार मिलने की अनुमति मिली है. उसके वकील ने हिरासत की अमानवीय स्थिति की आलोचना की है और बताया कि उन्हें सीरिया से अपहरण कर लेबनान लाया गया था.

हाल ही में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर निमोनिया और लीवर में सूजन है. यह पहली बार है कि 10 साल में उन्होंने जेल से बाहर रात बिताई.

जून में भी किया था रिहाई का अनुरोध

इस साल जून में उनके वकील ने रिहाई के लिए नया अनुरोध दायर किया था. हालांकि, इमाम सद्र और शेख याकूब के परिवार ने उनकी रिहाई का विरोध किया, बद्रद्दीन परिवार का समर्थन इस लंबे समय से रुके मामले में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. वकील बायोन के अनुसार, मामले में पर्याप्त सबूत नहीं हैं और 2017 के बाद से किसी भी जज ने हैन्निबल से मुलाकात नहीं की. फिलहाल, वो शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन लेबनानी कोर्ट और नई सरकार से न्याय की उम्मीद बनाए हुए हैं.

कौन हैं हैन्निबल गद्दाफी?

मुअम्मर गद्दाफी के पांचवें और सबसे छोटे बेटे हैन्निबल गद्दाफी हैं. उनका जन्म 1975 में हुआ था.

CDC चीफ डॉक्टर खैली ने किया अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का दौरा, स्वामी दास ने राष्ट्रपति नाहयान का जताया आभार

स्वामी ब्रह्मविहारी दास ने इस प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मंदिर का गहन भ्रमण कराते हुए प्रेम, शांति और सद्भाव की परियोजना के व्यापक दृष्टिकोण को भी साझा किया. यह दौरा UAE के लंबे समय से चले आ रहे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, अंतर धार्मिक संवाद और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के दीर्घकालिक मूल्यों पर चर्चा के लिए एक सशक्त मंच बना.

एजेंसी

सोची (रूस)। अंतर धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक समावेशिता के प्रति संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने वाले एक अहम कदम के रूप में सामुदायिक विकास विभाग (डीसीडी) के प्रमुख डॉक्टर मुगीर खामिस अल खैली ने 2 अक्टूबर (गुरुवार) को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अबू धाबी स्थित प्रतिष्ठित बीएपीएस हिंदू मंदिर का दौरा किया. स्वामी ब्रह्मविहारी दास ने इस दौरान राष्ट्रपति अल नाहयान का आभार भी जताया.

स्वामी ब्रह्मविहारी दास ने इस विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मंदिर का गहन भ्रमण कराते हुए प्रेम, शांति और सद्भाव की परियोजना के व्यापक दृष्टिकोण को भी साझा किया. यह दौरा संयुक्त अरब अमीरात के लंबे समय से चले आ रहे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, अंतर धार्मिक संवाद और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के दीर्घकालिक मूल्यों पर चर्चा के लिए एक सशक्त मंच बना, जो देश की वैश्विक छवि को सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में उभारता है.

स्वामी ने राष्ट्रपति अल नाहयान का जताया आभार

इस यात्रा के दौरान, स्वामी ब्रह्मविहारी दास ने संयुक्त अरब अमीरात के महामहिम राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के प्रति उनके अटूट समर्थन और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए गहरा आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने मंदिर के विकास के आगामी चरणों और अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में इसकी बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया. डॉक्टर अल खैली और उनकी टीम ने मंदिर को एकता के प्रतीक के रूप में अभिनंदित किया और इसकी उन सराहनीय कोशिशों की खुलकर तारीफ की, जो अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों को साझा मानवीय मूल्यों का उत्सव मनाने हेतु एकत्र करते हैं.

सामुदायिक एकजुटता की भावना

सामुदायिक विकास विभाग (डीसीडी) प्रतिनिधिमंडल ने सामुदायिक एकजुटता को प्रोत्साहित करने और संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता एवं समावेशिता के दृष्टिकोण को बढ़ाने में मंदिर के सकारात्मक योगदान को मान्यता भी दी. यूएई के इस प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा बहुसांस्कृतिक अमीरात की संरचना में सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करने के लिए आस्था-आधारित संस्थाओं और शासकीय संस्थाओं के बीच सहयोगी कोशिशों को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध करता है.

इससे पहले भी डॉक्टर मुगीर खामिस अल खैली इस बीएपीएस हिंदू मंदिर का दौरा कर चुके हैं. नवंबर 2023 में डॉक्टर खैली ने मोहम्मद अल बलूशी और डीसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंदिर का दौरा किया था. मंदिर स्थल पर जाने से पहले, डॉक्टर खैली और स्वामी ब्रह्मविहारी दास ने एक साथ मिलकर दुनिया भर से आए लोगों द्वारा रखी गई ईंटों पर पुष्प वर्षा की, साथ ही शांति और सद्भाव के लिए उनकी प्रार्थनाओं का सम्मान किया.

सऊदी-कतर और ईरान शांत फिर मिस्र क्यों ले रहा इजराइल से पंगा?

एजेंसी

वाशिंगटन। मिडिल ईस्ट में अब इजराइल का एक नए देश के साथ तनाव बढ़ रहा है. यह देश न तो कतर है और न ही ईरान, बल्कि इजिप्ट (मिस्त्र) है. दरअसल इजिप्ट ने सिनाई प्रायद्वीप पर सेना को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

खतरा इसिलए क्योंकि सिनाई प्रायद्वीप लंबे समय से इजिप्ट और इजराइल के बीच शांति बनाए रखने वाला माना जाता रहा है. इजराइल इसे कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन मान रहा है क्योंकि सिनाई के जोन क और ष्ट में सैन्य बढ़त पहले कभी इतनी भारी नहीं देखी गई. इजिप्ट के इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं खासकर तब जब सऊदी अरब, कतर और ईरान फिलहाल इजराइल से कोई सीधे युद्ध या टकराव नहीं चाहते. तो आखिर इजिप्ट क्यों भिड़ रहा है?

पहले समझिए कैंप डेविड समझौता क्या है?

कैम्प डेविड समझौते मिस्र और इजराइल के बीच शांति स्थापित करने वाला ऐतिहासिक समझौता था. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी

कार्टर की मध्यस्थता में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर साद और इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाचेम बगिन ने इसे 1978 में कैम्प डेविड में हस्ताक्षरित किया. इस समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटाया, जबकि मिस्र ने इजराइल को मान्यता दी. इसके साथ ही सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सिनाई को असैन्य क्षेत्र घोषित किया गया. यह समझौता मध्य पूर्व में पहली बार अरबइजराइल युद्धों के बाद स्थायी शांति की नींव माना गया.

मिस्त्र की क्या दलील है?

पहला- मिस्र की तरफ से ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण के लिए बताया गया है. सरकार का कहना है कि सैनिकों की तैनाती आतंकवाद, तस्करी और संभावित गाजा पलायन को रोकने के लिए जरूरी है. इजिप्ट का मानना है कि इजराइल गाजा को असुरक्षित बनाकर लाखों लोगों को सिनाई में धकेल सकता है. राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी ने इसे रेड लाइन कहा है, और स्पष्ट किया कि यह मिस्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.

अफगान शरणार्थियों पर बेरहम हुआ पाकिस्तान, बंद किए कैंप और दी घर जलाने की धमकी

एजेंसी

पाकिस्तानी । पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के कई लंबे समय से चल रहे अफगान शरणार्थी कैंपों को बंद कर दिया है. इनमें लोअरलाई, गारदी जंगल, सारानन, झोब, कलाँ-ए-सैफुल्लाह, पिशीन और मुस्लिम बाग शामिल हैं.

इन कैंपों में रह रहे अफगान शरणार्थियों को उनके घरों और दुकानों से निकाला गया और उनकी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया. लोगों को धमकी तक दी गई कि अगर घर नहीं छोड़ा तो सब कुछ जला देंगे.

जबरन निकाले जा रहे हैं अफगानी

चमन में अफगान शरणार्थियों की मदद करने वाले नागरिक संगठन के वली मोहम्मद ने कहा कि मैं पाकिस्तानी सरकार से अपील करता हूँ कि शरणार्थियों को जबरन बाहर निकालते समय मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए. दुनिया के दूसरे देश अफ़ग़ानियों को पांच साल में नागरिकता दस्तावेज़ दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यह दशकों बाद भी नहीं हुआ. बलूचिस्तान के इन कैंपों से निकाले गए शरणार्थियों का कहना है कि वे अफागानिस्तान लौटे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा. उन्हें तत्काल आश्रय और मानवतावादी मदद की आवश्यकता है.

5 दिन में 13 हजार अफगानियों को निकाला

Tolo News की एक खबर के मुताबिक अधिकारी कुछ सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अफगान शरणार्थियों को जबरन पाकिस्तान से निकाले जाने की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं. अधिकारियों के अनुसार, सिर्फ पिछले पांच दिनों में 13,504 शरणार्थी, जिनमें सैकड़ों पूर्व कैदी भी शामिल हैं. ये सभी सीमा के माध्यम से अफगानिस्तान लौटे हैं. शरणार्थियों की यह मुश्किलें और बढ़ती वापसी चिंता का विषय हैं और स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तत्काल मदद की आवश्यकता है.

क्यों अफगानियों पर बेरहम हुआ पाकिस्तान

दरअसल 2023 में पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों में अपने देश में घुसने वाले लगभग 40 लाख अफगानों को वापस भेजने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की थी. दरअसल पिछले तीन सालों में पाकिस्तान और पड़ोसी अफगानिस्तान के संबंध बिगड़ गए हैं. इस्लामाबाद का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमलों को रोकने में नाकाम रही हैं.

जापान में पहली बार महिला PM बनेंगी, जानिए भारत, चीन और अमेरिका पर क्या है उनका स्टैंड

जापान को पहली महिला पीएम मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के 7 सितंबर को इस्तीफा देने के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने 4 अक्टूबर को अपने नए अध्यक्ष का चुनाव किया. इसी चुनाव में ताकाइची ने जीत हासिल की है.

एजेंसी

जापान । जापान के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने जा रही है. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री सना ए ताकाईची को अपनी नई अध्यक्ष चुना है. जापान में बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए लगभग तय है कि ताकाईची ही देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी.

ताकाईची को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का करीबी माना जाता है, जो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे. साने की पहचान एक कंजर्वेटिव नेता की रही है. उन्होंने 10 साल में जापान की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने की योजना पेश की है. आइए इसी बहाने जान लेते हैं उनकी विदेश नीति, खासकर भारत, चीन और अमेरिका के संदर्भ में. इन तीनों देशों को लेकर उनकी राय क्या है?

भारत को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानती हैं

भारत और जापान के बीच पहले से ही मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं, और ताकाईची इन संबंधों को और बढ़ाने की इच्छुक हैं. उनका मानना है कि दोनों देशों को मिलकर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करना चाहिए. The Diplomat की एक खबर के मुताबिक उन्होंने ताइवान की यात्रा के दौरान भारत, ताइवान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच एक ÷क्वासी-सुरक्षा गठबंधन÷ बनाने का प्रस्ताव दिया था, ताकि आपसी हितों की रक्षा की जा सके.

चीन की हैं कट्टर विरोधी

सना ए ताकाईची अपने चीन के खिलाफ कड़े रुख के लिए जानी जाती हैं. वे अक्सर टोक्यो के यासुकुनी श्राइन जाती हैं, जो जापान के युद्ध में मारे गए सैनिकों को सम्मानित करता है और अक्सर पड़ोसी देशों को नाराज़ कर देता है. जैसे पूर्व प्रधानमंत्री आबे ने जापान की सेना को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए थे, वैसे ही ताकाईची भी चीन के खिलाफ देश की सैनिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वे चीन को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानती हैं.

ट्रंप के साथ हुए ट्रेड डील से नाखुश

अमेरिका के साथ उनके रिश्ते भी मजबूत हैं, लेकिन वे कुछ व्यापारिक समझौतों पर पुनर्विचार की पक्षधर हैं. उनका मानना है कि जापान को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को समान साझेदारी के रूप में देखना चाहिए, न कि एकतरफा निर्भरता के रूप में. ताकाइची हाल ही में ट्रंप प्रशासन के साथ हुए ट्रेड डील के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि इस पर फिर से बातचीत की जानी चाहिए. दरअसल जापान और अमेरिका के बीच अगस्त में डील हुई थी. इसमें जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया था.

अमेरिका छोड़ने के लिए 2 लाख रुपये, किन लोगों को ये रकम दे रही ट्रंप सरकार?

अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अब देश में मौजूद अकेले प्रवासी बच्चों (unaccompanied migrant children) को अपने देश लौटने के लिए 2 लाख से ज्यादा की रकम देने की पेशकश की है. हालांकि, मेक्सिको से आने वाले बच्चे इसके लिए पात्र नहीं होंगे. इमिग्रेशन एडवोकेट्स ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है.

एजेंसी

अमेरिका । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की सत्ता संभालने के बाद से ही अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं. साथ ही वो प्रवासियों को डिपोर्ट करने पर जोर दे रहे हैं. इस बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अमेरिका में मौजूद अकेले प्रवासी बच्चों (unaccompanied migrant children) को अपने देश लौटने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.

अकेले प्रवासी बच्चों अपने देश लौटने के लिए अमेरिका प्रशासन प्रोत्साहित करने के लिए एकमुश्त 2,500 डॉलर (2 लाख 21 हजार 910 रुपये) की मदद देने की पेशकश कर रहा है.

किसे दी जाएगी रकम?

शुक्रवार को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के ऑफिस ऑफ रिफ्यूजी रिसेटलमेंट की ओर से प्रवासी शेल्टरों को भेजे गए पत्र में इस बात की जानकारी दी गई. पत्र में कहा गया कि 14 साल या उससे ऊपर के प्रवासी बच्चे अगर अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़कर अपने देश लौटना चाहें तो उन्हें यह "रीसेटेलमेंट सपोर्ट स्टाइपेंड" दिया जाएगा.

अधिकारियों ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सटीक रकम का खुलासा नहीं किया. यह कदम ट्रंप प्रशासन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत स्वैच्छिक निर्वासन (voluntary deportation) को बढ़ावा दिया जा रहा है.

इस साल की शुरुआत में, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने उन एडल्ट प्रवासियों (migrants) को 1,000 डॉलर का भत्ता (stipend) देने की पेशकश की थी, जो "स्वेच्छा से वापसी" (self-deportation) चुनते हैं. यह योजना अमेरिकी विदेश विभाग से मिले 250 मिलियन डॉलर के फंड ट्रांसफर के जरिए चलाई गई थी.

मेक्सिको के बच्चे नहीं होंगे पात्र

रॉयटर्स के अनुसार, एक ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) अधिकारी ने बताया कि 2,500 डॉलर की पेशकश शुरुआत में 17 साल के बच्चों के लिए की जा रही है. मेक्सिको से आने वाले बच्चे इसके लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे शुक्रवार तक अमेरिका छोड़ने के लिए पहले ही स्वेच्छा से तैयार हो गए थे, उन्हें भी यह योजना कवर करेगी.

पत्र में क्या-क्या कहा गया?

पत्र में कहा गया है कि भुगतान सिर्फ तभी किया जाएगा जब एक इमिग्रेशन जज उस अनुरोध को मंजूरी देंगे और बच्चा सुरक्षित रूप से अपने देश लौट जाएगा.

अमेरिकी संघीय कानून के तहत, जो प्रवासी बच्चे बिना माता-पिता या कानूनी अभिभावक के अमेरिका की सीमा पर आते हैं, उन्हें "अनअकंपनिड" (unaccompanied) माना जाता है और उन्हें सरकारी शेल्टर (shelters) में रखा जाता है, जब तक कि वे परिवार से न मिल जाएं या उन्हें फोस्टर केयर में न भेजा जाए. गुरुवार तक, 2,100 से ज्यादा अनअकंपनिड बच्चे अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) की हिरासत में थे.

जमकर हो रही आलोचना

इमिग्रेशन एडवोकेट्स ने इस कदम की कड़ी आलोचना की. "किड्स इन नीड ऑफ डिफेंस" की अध्यक्ष वेंडी यंग ने कहा कि यह स्टाइपेंड एक "क्रूर तरीका" है, जो कमजोर बच्चों को मिली कानूनी सुरक्षा को कमजोर करता है.

उन्होंने बयान में कहा, अमेरिका में सुरक्षा की तलाश में आए अनअकंपनिड बच्चों को हमारी सुरक्षा मिलनी चाहिए, न कि उन्हें मजबूर किया जाए कि वो उन्हीं हालात में वापस लौट जाएं जिनसे उनकी जान और सुरक्षा खतरे में पड़ी थी.

हालांकि, अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) ने इस प्रोग्राम का बचाव किया. HHS के कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंड्रयू निक्सन ने कहा कि यह योजना बच्चों को अपने भविष्य के बारे में चुनाव करने और समझदारी से निर्णय लेने का विकल्प देती है.

चीनी सैनिकों के पास आया ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, देखता रह गया अमेरिका

एजेंसी

अमेरिका । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऐलान किया था. इस मिसाइल शील्ड को अब अमेरिका से पहले चीन ने तैयार कर लिया है. गोल्डन डोम का प्लान जहां अमेरिका ने पहले पेश किया. वहीं, इसको तैयार करने में चीन आगे निकल गया.

एक चीनी रिसर्च टीम का दावा है कि उसने एक वर्किंग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रोटोटाइप विकसित किया है, जो देश को दुनिया में कहीं भी हवाई खतरों (airborne threats) का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बना सकता है. टीम का कहना है कि इसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (क्क) की ओर से पहले ही तैनात किया जा चुका है.

अमेरिका से आगे निकला चीन

हालांकि, यह अभी शुरुआती फेज में है, यह सिस्टम बड़ी डेटा तकनीकों (big data) में हुए इनोवेशन का इस्तेमाल करके की तरह के सेंसर की जानकारी को इकट्ठा करता है. अगर यह सफल होता है, तो यह पहला एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा और यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा योजना के लागू होने से काफी पहले होगा.

डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर

गोल्डन डोम एक डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली वॉर्निंग सिस्टम है. इसे ग्लोबल रडार की तरह समझ जा सकता है, जो अंतरिक्ष, समुद्र, हवा और जमीन पर हजारों सेंसरों से डेटा इकट्ठा करता है. सैटेलाइट, रडार, विमान और जमीन पर लगे सेंसर एक साथ मिलकर एक बड़ा डेटा प्लेटफॉर्म बनाते हैं. यह सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एक साथ दुनिया भर से 1000 मिसाइल लॉन्च को ट्रैक कर सकता है. अगर कोई मिसाइल चीन की ओर आती है, तो यह उसका तुरंत पता लगा लेता है.

ट्रंप ने किया था योजना का ऐलान

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम योजना को लेकर मई के महीने में ऐलान किया था. यह 175 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है. लेकिन, अभी तक इस सिस्टम का कोई आर्किटेक्चर (architecture) सामने नहीं आया है, कांग्रेसी बजट कार्यालय ने चेतावनी दी है कि इसकी असल में लागत लगभग तीन गुना ज्यादा हो सकती है.

चीन ने डिफेंस सिस्टम को लेकर दावा ऐसे समय में किया है जब वॉशिंगटन में अपने समान सैन्य प्रतिद्वंद्वियों, खासकर चीन की क्षमताओं को लेकर

चिंता बढ़ रही है. बीजिंग के पास दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल बेड़े में से एक है और उसने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में अमेरिका से बढ़त बना ली है. एक वर्किंग चीनी वैश्विक डिफेंस सिस्टम अमेरिका को असंतुलन में डाल सकती है, खासकर जब एशिया-पैसिफिक में ताइवान जैसे विवादित क्षेत्रों पर तनाव बढ़ रहा है.

डिफेंस सिस्टम से चीन को मिलेगी ताकत

इस सिस्टम से चीन को काफी ताकत मिलेगी. इसे दुनिया में कहीं से भी लॉन्च की जाने वाली एक हजार तक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है. पारंपरिक सुरक्षा सिस्टम के उलट, जो अक्सर किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित रहती हैं, यह प्रोटोटाइप सचमुच वैश्विक पहुंच का दावा करता है और यह वैश्विक मिसाइल सुरक्षा की दिशा में एक साहसिक कदम माना जा रहा है.

यह प्लेटफॉर्म विभिन्न जगहों पर फैले हुए उपकरणों को जोड़कर काम करता है. यह सैटेलाइट, राडार, कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपकरणों से डेटा इकट्ठा करता है, जो जमीन, समुद्र, हवा और अंतरिक्ष में हैं.

यह रियल टाइम में मिसाइल की स्पीड और मार्ग को मैप कर सकता है, यह निर्धारित कर सकता है कि टारगेट असली वारहेड है या बहकाने वाला डिकॉय, जानकारी इंटरसेप्शन यूनिट्स तक पहुंचा सकता है. भले ही नेटवर्क बाधित या भीड़-भाड़ वाला हो, सिस्टम Quick UDP Internet Connections (QUIC) जैसे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके सूचना को तेजी और सुरक्षा के साथ दे सकता है.

अमेरिका ने इस डिफेंस सिस्टम की रूपरेखा तैयार की थी. लेकिन, चीन एक प्रोटोटाइप के साथ आगे निकल गया है. पिछले 10 साल में, बीजिंग ने हाइपरसोनिक हथियारों जैसे क्षेत्रों में वॉशिंगटन को पीछे छोड़ दिया है, जबकि कई अमेरिकी प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ने की समस्याएं रही हैं.

सेना ने टेस्ट किया शुरू

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पहले से ही कई स्थानों पर इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का टेस्ट कर रही है. रिसर्चर्स के अनुसार, इस सिस्टम की मदद से इकट्ठा किए गए डेटा से ढ्ढ को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे सिस्टम समय के साथ खतरों को पहचानने और इंटरसेप्शन गाइड करने में और बेहतर होगा.

हालांकि, प्रोटोटाइप की तैनाती का मतलब यह नहीं है कि चीन के पास पूरी तरह से वर्किंग वैश्विक मिसाइल शील्ड है. जहां चीन इस शील्ड को लेकर आगे बढ़ रहा है. वहीं, अमेरिका की गोल्डन डोम योजना अभी कागज पर है, बीजिंग ने एक काम करने वाला मॉडल पेश कर दिया है.

क्या ज्यादा कमाई से बेहतर होता है क्रेडिट स्कोर? ये रही सच्चाई

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इनकम और क्रेडिट स्कोर के बीच कोई कनेक्शन है? कॉमन बिलीफ के उलट, इन दोनों में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. हां, हाई इनकम जरूर आपकी बिल्स और लोन ईएमआई को टाइम पर पे करने की अबिलिटी को बूस्ट करती है, जिससे आपके क्रेडिट स्कोर पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है, लेकिन इसका स्कोर पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है.

एजेंसी

नई दिल्ली। ज्यादा कमाई होने के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति समय पर ऋण चुकाने में असफल रहता है, क्रेडिट कार्ड की सीमा का अत्यधिक उपयोग करता है, या पुराने क्रेडिट खाते बंद कर देता है, तो उसका क्रेडिट

स्कोर कम हो सकता है.

कम आय वाला व्यक्ति यदि भुगतान में अनुशासित रहता है और क्रेडिट का सही मैनेजमेंट करता है, तो वह उच्च क्रेडिट स्कोर बनाए रख सकता है. व्यक्ति को अपनी आय के अनुपात में ही ऋण लेना चाहिए. उदाहरण के लिए, उच्च आय वाला व्यक्ति अधिक क्रेडिट सीमा ले सकता है, लेकिन उसे कुल सीमा के 30त्न से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए. कम क्रेडिट लेने से चुकाना आसान होता है.

कई क्रेडिट कार्ड यूजर्स भविष्य की अनुमानित आय के आधार पर नया ऋण ले लेते हैं, जो जोखिम भरा हो सकता है.

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए जरूरी सलाह, ऐसे चेक करें KYC स्टेटस

अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके ही लिए है. आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने निवेश की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

एजेंसी

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपनी केवाईसी (KYC) अपडेट रखना जरूरी है. केवाईसी अपडेट करने से पहले, उसकी स्थिति की जांच करना जरूरी है. आप किसी भी एएमसी या आरटीए की वेबसाइट पर अपना पैन नंबर डालकर इसकी जांच कर सकते हैं. आपकी केवाईसी स्थिति 'मान्य', 'पंजीकृत', 'होल्ड पर' या 'अस्वीकृत' के रूप में प्रदर्शित होगी.

इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी म्यूचुअल फंड या आरटीए की वेबसाइट पर जाना है जहां से आपने निवेश किया है. इससे बाद केवाईसी स्थिति लिंक की जांच करें और आप अपना 10 अंकों का पैन डालें. कैप्चा पर क्लिक करें. क्लिक के बाद केवाईसी का स्टेटस दिख जाएगा.

एक बार केवाईसी वेरीफाई हो जाने के बाद, आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है. आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कभी भी कोई भी लेनदेन कर सकते हैं.

आप बिना किसी परेशानी के अपने सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड निवेशों में लेनदेन जारी रख सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, जिसमें आपका पहले से कोई निवेश नहीं है, तो आपको दोबारा केवाईसी करानी होगी.

इसके अलावा अगर कभी केवाईसी स्टेटस होल्ड या रिजेक्टेड दिखे तो उसके लिए आपको बस म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर जाकर ऊपर बताए तारीके को फॉलो करना है. जैसे ही स्टेटस 'वैलिडेट' हो जाएगा, आप लेनदेन शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे.

पुराने बैंक खाते में फंस गया पैसा? ये रहा निकालने का आसान तरीका, एक-एक रुपया आएगा वापस

एजेंसी

नई दिल्ली। अगर आपके पास किसी बैंक खाते में कुछ पैसा है, लेकिन आपने दो साल से उस खाते का इस्तेमाल नहीं किया है. ऐसे में उस खाते का क्या होगा? वह खाता निष्क्रिय हो जाएगा और उसमें जमा पैसे को वापस पाना एक मुश्किल काम लग सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे पैसों को वापस पाने के सरल तरीके मौजूद हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब लोगों को उनके निष्क्रिय खातों से पैसा वापस दिलाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चला रहा है. RBI देश के हर जिले में अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच अनक्लेम्ड एसेट्स पर विशेष शिविर आयोजित करेगा.

क्या होता है निष्क्रिय खाता?

अगर किसी बैंक खाते में दो साल से लेकर दस साल तक कोई लेन-देन नहीं हुआ, तो वह निष्क्रिय माना जाता है. ऐसे खातों में पड़ा पैसा

बैंक को RBI के DEA Fund में ट्रांसफर करना पड़ता है. लेकिन चिंता की बात नहीं है. खाता धारक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी कभी भी इस पैसे का दावा कर सकते हैं, भले ही पैसा पहले ही DEA Fund में चला गया हो.

क्या है RBI का DEA Fund?

डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA)फंड की शुरुआत 24 मई 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने की थी. इस फंड में वह रकम जमा की जाती है जो किसी बैंक खाते में 10 साल या उससे ज्यादा समय से पड़ी रहती है और जिसे खाता धारक ने 10 साल से इस्तेमाल नहीं किया या क्लेम नहीं किया होता है. बैंक को यह पूरा पैसा, जिसमें अब तक का ब्याज भी शामिल होता है, DEA Fund में ट्रांसफर करना जरूरी होता है.

पैसा वापस पाने के आसान कदम

किसी भी बैंक शाखा में जाएं, भले ही वह आपकी पुरानी शाखा न हो. एक फॉर्म भरें और अपने KYC दस्तावेज (आधार, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस) जमा करें. बैंक आपकी जानकारी की जांच करेगा. जांच पूरी होने के बाद, आपको आपका पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाएगा.

ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार ने कसा शिकंजा, कैश ऑन डिलीवरी पर वसूला ज्यादा चार्ज, शोषण का आरोप

एजेंसी

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा कैश ऑन डिलीवरी (COD) ऑर्डर पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतों पर संज्ञान लिया है. विभाग ने इस प्रथा को डार्क पैटर्न करार देते हुए कहा कि यह उपभोक्ताओं को गुमराह करने और उनका शोषण करने का प्रयास है. उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.

मिली शिकायतों के अनुसार, कई उपभोक्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय यदि वे कैश-ऑन-डिलीवरी विकल्प चुनते हैं तो कंपनियां उनसे अलग से अतिरिक्त रकम वसूल रही हैं. विभाग ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए व्यापक जांच शुरू कर दी है. मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को शिकायतें मिली हैं कि ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कैश ऑन डिलीवरी पर ज्यादा चार्ज ले रहे हैं. यह उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला डार्क पैटर्न है. विस्तृत जांच शुरू की गई है और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक, संबंधित ई-कॉमर्स कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विभाग का कहना है कि भारत के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार बनाए रखना अनिवार्य है.

GST राहत से टूटा 10 सालों का रिकॉर्ड, नवरात्रि में लोगों ने की बंपर खरीदारी

एजेंसी

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार की ओर जीएसटी स्लैब में बदलाव कर लोगों को टैक्स में राहत देने का असर नवरात्रि पर देखने को मिला. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत की कंज्यूमर इकोनॉमी ने पिछले 10 सालों में इस बार नवरात्रि में सबसे ज्यादा बिक्री देखी है. जीएसटी स्लैब को रेशनलाइज करने से जरूरी और लक्जरी सामानों पर टैक्स का बोझ कम हुआ, जिससे लोग कॉन्फिडेंस के साथ खरीदारी कर रहे हैं. लोगों ने होम अप्लायंसेज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स अपग्रेड किए, जिससे डिमांड में जबरदस्त उछाल आया.

ऑटोमोबाइल कंपनियों को इस नवरात्रि में सबसे ज्यादा फायदा हुआ. जीएसटी में कटौती के बाद मारुति सुजुकी ने पिछले एक दशक में अपनी बेस्ट नवरात्रि सेल्स रिकॉर्ड की. उनकी बिक्री पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई. कंपनी ने 1,50,000 बुकिंग्स हासिल कीं और उम्मीद है कि ये 2,00,000 तक पहुंच जाएंगी. पिछले साल नवरात्रि में 85,000 गाड़ियां बिकी थीं. इस बार

फेस्टिवल के पहले 8 दिनों में 1.65 लाख गाड़ियों की डिलीवरी हुई, जिसमें पहले दिन ही 30,000 कार्स बिकीं, जो 35 सालों में मारुति का बेस्ट सिंगल-डे परफॉर्मेंस है.

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 60त्न की रिटेल सेल्स ग्रोथ देखी. हुंडई में क्रेटा और वेन्यू की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से स्क्रू सेल्स उनकी टोटल सेल्स का 72त्न से ज्यादा थी.

हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम में कस्टमर्स की संख्या दोगुनी हो गई, खासकर कम्यूटर टू-व्हीलर्स में अच्छी ग्रोथ देखी गई. टाटा मोटर्स ने 50,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जिसमें अल्ट्रोज, पंच, नेक्सन और टियागो मॉडल्स टॉप पर रहे.

बजाज ऑटो ने भी फेस्टिव सीजन में अच्छी सेल्स रिकॉर्ड की.

Lenskart को सेबी से मिली मंजूरी, नवंबर में आएगा 8,000 करोड़ का IPO

एजेंसी

नई दिल्ली। चश्में की रिटेल कंपनी लेंसकार्ट को सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से अपने IPO को लाने को लेकर हरी झंडी मिल गई है. सूत्रों के मुताबिक, कंपनी अगले कुछ हफ्तों में अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस दाखिल करेगी और नवंबर के मध्य तक शेयर बाजार में लिस्ट होने की योजना है.

लेंसकार्ट ने जुलाई में सेबी के पास इश्यू के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा किया था, जिसके जरिए वो 2,150 करोड़ रुपये की नई पूंजी जुटाना चाहती है. इसके अलावा, कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल, नेहा बंसल, सुमीत कपाही और अमित चौधरी, साथ ही सॉफ्टबैंक, प्रेमजी इन्वेस्ट, टेमासेक, केदारा कैपिटल और अल्फा वेव ग्लोबल जैसे शेयरधारक, ऑफर-फॉर-सेल के जरिए 132.3 मिलियन शेयर बेचेंगे. कुल मिलाकर, इस आईपीओ का साइज 7,500-8,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है.

ये इस साल टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा. कोटक महिंद्रा, मॉर्गन स्टेनली, सिटी, एवेंडस कैपिटल और इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज इस आईपीओ के मर्चेंट बैंकर हैं .गुरुग्राम की इस कंपनी का आईपीओ इस साल के कई बड़े आईपीओ में

सबसे बड़ा होगा. स्टॉकब्रोकिंग फर्म ग्रो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो, पेमेंट कंपनी फोनपे और एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला भी लिस्टिंग की तैयारी में हैं, लेकिन उन्होंने सेबी की गोपनीय फाइलिंग प्रक्रिया चुनी है.

कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति

लेंसकार्ट ने वित्त वर्ष 2025 में मुनाफा कमाया है, जिसमें 297 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, जबकि पिछले साल वित्त वर्ष 2024 में 10 करोड़ रुपये का घाटा था. कंपनी का रेवेन्यू भी 22% बढ़कर 5,428 करोड़ रुपये से 6,625 करोड़ रुपये हो गया. ईटी स्टार्टअप अवार्ड्स 2024 में स्टार्टअप ऑफ द ईयर जीतने वाली लेंसकार्ट इस आईपीओ से मिलने वाले 272 करोड़ रुपये से भारत में नए स्टोर खोलेगी.

साथ ही, 591 करोड़ रुपये अपने 2,700 से ज्यादा मौजूदा स्टोर्स के किराए, लीजिंग और अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल करेगी. कुछ राशि अधिग्रहण के लिए भी रखी गई है.

अडानी-अंबानी के पारिवारिक दफ्तर को देना होगा खर्च का ब्योरा? क्या है इस खबर की सच्चाई

सेबी ने फैमिली ऑफिसेज के रेगुलेशन को लेकर चल रही खबरों के बीच बयान जारी किया है. मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि हम किसी ऐसे नियम पर विचार नहीं कर रहे हैं. सेबी ने इसके इर्द-गिर्द चली खबरों का खंडन किया है.

एजेंसी

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मीडिया में चल रही उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अंबानी-अडानी जैसे बड़ी बिजनेस फैमिलीज को अपने खर्च का ब्योरा देना होगा. लेकिन इस पर सेबी का बयान आया है. बयान में रेगुलेटरी बॉडी वह पारिवारिक कार्यालयों के लिए किसी नियामक ढांचे पर विचार नहीं कर रहा है. यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि बाजार नियामक पारिवारिक कार्यालयों को अपने दायरे में लाने की संभावना तलाश रहा है. हालांकि, सेबी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मार्केट रेगुलेटर सेबी अब फैमिली ऑफिस को अपने रडार पर लाने की सोच रहा है, क्योंकि भारत के अरबपति स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा रोल प्ले करने लगे हैं. कुछ लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि सेबी इस बारे में बात कर रहा है कि फैमिली ऑफिस को अपनी संपत्ति, इनवेस्टमेंट और रिटर्न की जानकारी देनी होगी. साथ ही, उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाकर इनवेस्टमेंट को रेगुलेट करने की बात भी चल रही है.

रिपोर्ट में किया गया दावा

रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस साल की शुरुआत में सेबी ने कुछ बड़े फैमिली ऑफिस के साथ मीटिंग की और दूसरों से लिखित में प्रपोजल मांगे, ताकि ये समझ सके कि ये बड़े परिवार पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज में कैसे इनवेस्ट करते हैं और इससे क्या रिस्क हो सकते हैं. सेबी ने एक

बयान में कहा कि हम अभी इस मामले में कोई जांच या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. भारत में फैमिली ऑफिस के लिए अभी कोई खास नियम नहीं हैं, इसलिए सूत्रों ने बताया कि नए नियम कब और कैसे बनेंगे, ये अभी साफ नहीं है. सेबी का ये कदम दिखाता है कि भारत के सुपर-रिच परिवार अब इतने बड़े इनवेस्टर बन गए हैं कि उनके इनवेस्टमेंट मार्केट में हलचल मचा सकते हैं.

भारतीय इंडस्ट्री में कई फैमिली ऑफिस स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी और आईपीओ में बड़े इनवेस्टर बनकर उभरे हैं. सूत्रों के मुताबिक, सेबी ने कुछ बड़े फैमिली ऑफिस के साथ बातचीत में ये भी पूछा कि क्या उन्हें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (त्तक्चक्र) की तरह हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए. इससे उन्हें आईपीओ में प्राथमिकता मिलेगी और वे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियों या विदेशी बड़े फंड्स की तरह मार्केट में बराबरी का मौका पा सकेंगे.

पहले सेबी ने अनरेगुलेटेड फैमिली इनवेस्टर को ऐसी सुविधा देने से मना किया था.

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने बदला नियम, कर्मचारियों के इस भत्ते पर होगा असर

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भत्तों पर असर डालने वाला एक बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने ड्रेस भत्ता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा. डाक विभाग ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है, जिसमें रिटायर्ड और नए भर्ती कर्मचारियों के लिए स्थिति स्पष्ट की गई है.

यह नया आदेश मध्य वर्ष में जॉइन या रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है. अब उन्हें यह चिंता नहीं रहेगी कि उनके ड्रेस भत्ते का भुगतान कब और कितना मिलेगा, क्योंकि नियम अब स्पष्ट हो चुके हैं.24 सितंबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी साल के बीच में नौकरी जॉइन करते हैं या रिटायर होते हैं, उन्हें अब अनुपातिक आधार पर ड्रेस भत्ता दिया जाएगा. ड्रेस भत्ता वह राशि है जो सरकार उन कर्मचारियों को देती है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहननी होती है. वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में जारी एक सर्कुलर में बताया था कि ड्रेस भत्ता अब पुराने कई भत्तों को मिलाकर दिया जाता है. जैसे कपड़ा भत्ता, बेसिक इक्विपमेंट भत्ता, यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता, गाउन भत्ता और जूता भत्ता.

वित्त मंत्रालय से मंजूरी

जून 2025 में जारी एक पुराने आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है और तब तक 2020 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे. अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जैसे नए भर्ती कर्मचारी साल के अनुसार ड्रेस भत्ता पाते हैं, वैसे ही साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी अनुपातिक ड्रेस भत्ता पाएंगे.

जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है भत्ता

डाक विभाग ने बताया कि ड्रेस भत्ता जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है. इसलिए कई ऐसे कर्मचारी जो इस साल रिटायर हो रहे हैं, उन्हें पहले ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है. नए नियमों के तहत अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों से जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी, लेकिन 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई रिकवरी नहीं होगी.

नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टीकरण

विभाग ने यह भी साफ किया है कि जो कर्मचारी जुलाई 2025 से पहले जॉइन करेंगे, उन्हें जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा. कुछ जगह यह देखा गया था कि पिछले साल का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया, इसलिए अब उसे सही करने के निर्देश दिए गए हैं.

बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब फटाफट हो जाएंगे चेक क्लीयर...घंटे भर में आएगा पैसा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लिरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नया नियम यानी 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है. नए नियम के तहत अब कस्टमर्स का चेक कुछ ही घंटों में क्लीयर हो जाएगा. पहले इसमें 2 दिन तक का समय लगता था. आरबीआई ने बताया कि एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा. इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा.

क्लियरिंग हाउस, चेक की तस्वीरें उन बैंको को निरंतर आधार पर जारी करेगा, जहां का चेक होगा, जिससे प्रत्येक चेक का निपटान वर्तमान टी+1-दिवसीय क्लियरिंग चक्र के बजाय, लगभग वास्तविक समय के आधार पर किया जा सकेगा. ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर और वित्तीय सेवा जोखिम प्रमुख विवेक अय्यर ने कहा कि इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि धनराशि कुछ ही घंटों में जमा हो जाए, जिससे ग्राहकों को धनराशि तक त्वरित पहुंच प्राप्त होगी.

पहला फेज

इससे उन इलाकों को खास फायदा होगा जहां डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह तैयार नहीं है.

बैंकों की बैक-एंड टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया गया है ताकि नई सिस्टम में आसानी से ट्रांजिशन हो सके. इसको दो फेज में शुरू किया गया है. पहला फेज 4 अक्टूबर, 2025 से 2 जनवरी, 2026 तक होगा. इस दौरान, जिन बैंकों को चेक मिलेंगे, उन्हें पुष्टिकरण सत्र खत्म होने तक चेक की कन्फर्मेशन करनी होगी. अगर इस समय में चेक कन्फर्म नहीं होता, तो उसे स्वीकार मान लिया जाएगा और सेटलमेंट के लिए शामिल किया जाएगा. इस फेज में सभी चेकों का आइटम एक्सपायरी टाइम शाम 7 बजे होगा.

दूसरा फेज 3 जनवरी, 2026 से शुरू होगा इसमें चेकों का आइटम एक्सपायरी टाइम बदलकर ञ्ज+3 घंटे कर दिया जाएगा. अगर कोई चेक तीन घंटे में कन्फर्म नहीं होता, तो उसे स्वीकार मान लिया जाएगा और दोपहर 2 बजे सेटलमेंट के लिए शामिल किया जाएगा. बैंकों की पॉजिटिव कन्फर्मेशन और स्वीकार किए गए चेकों के आधार पर, सुबह 11 बजे से पुष्टिकरण सत्र खत्म होने तक हर घंटे सेटलमेंट जारी होंगे. प्रस्तुतकर्ता बैंक इन सेटलमेंट्स को प्रोसेस करेंगे और सामान्य सिक्योरिटी चेक के बाद, सक्सेसफुल सेटलमेंट के एक घंटे के अंदर कस्टमर्स को पेमेंट कर देंगे. चेक ट्रंकेशन सिस्टम (ष्टञ्जस्) के तहत वित्त वर्ष 25 में 609.54 मिलियन ट्रांजैक्शन्स हुए, जिनका कुल मूल्य 71.13 ट्रिलियन रुपये था. वहीं, वित्त वर्ष 26 में अब तक ट्रांजैक्शन्स का मूल्य ?29.39 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है.

क्या होता है COD चार्ज? जिससे ई-कॉमर्स कंपनियां कर रही हैं कमाई

एजेंसी

नई दिल्ली। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा कैश-ऑन-डिलीवरी (COD) ऑर्डर पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने की जांच शुरू की है. इसे "डार्क पैटर्न" कहा गया है, जो कस्टमर्स को गुमराह करता है और उनका फायदा उठाता है. आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि ये सीओडी चार्ज और डार्क पैटर्न क्या होता है और इसके जरिए ई-कॉमर्स कंपनियां कमाई कैसे करती हैं. इस साल की शुरुआत में कस्टमर्स ने शिकायत की थी कि कुछ प्लेटफॉर्म्स COD ऑर्डर पर 'कैश हैंडलिंग चार्ज' लगा रहे हैं. जुलाई में Zepto के यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की थी कि चेकआउट के वक्त छिपे हुए चार्जेज लगाए जा रहे हैं. ये चार्जेज "ड्रिप प्राइसिंग" का हिस्सा हो सकते हैं, जो भारत में 13 डार्क पैटर्न्स में से एक है और गैरकानूनी माना जाता है.

क्या होता है COD चार्ज?

कैश-ऑन-डिलीवरी (COD) एक भुगतान विधि है जिसमें ग्राहक ऑर्डर डिलीवरी के समय नकद या डिजिटल पेमेंट करता है. ई-कॉमर्स कंपनियां इसे ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी में भरोसा बढ़ाने और सुविधा प्रदान करने के लिए ऑफर करती हैं. वे डिलीवरी पार्टनर के साथ मिलकर COD लागू करती हैं, जहां कूरियर भुगतान एकत्र करता है. उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं तो वहां पर पैसा देने के दो-तीन ऑप्शन होते हैं एक तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का होता एक यूपीआई से पेमेंट करने का विकल्प होता और एक कैश-ऑन-डिलीवरी का होता है. अगर आप सीओडी चुनते हैं और मान लीजिए 1500 रुपये का मोबाइल कवर ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी के समय आपको डिलीवरी पार्टनर को 1500 रुपये कैश में या नकद देने होंगे.

डार्क पैटर्न क्या हैं?

डार्क पैटर्न वो ट्रिक्स हैं, जो वेबसाइट्स या ऐप्स में यूज किए जाते हैं ताकि कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया जाए. ये छिपे हुए डिजाइन या भ्रामक भाषा हो सकती है, जो यूजर्स को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करती है, जो वो नहीं चाहते हैं.

डिलीवरी चार्ज को आखिरी स्टेप तक छिपाना.

सहमति बॉक्स पहले से चेक करना.

सिर्फ 1 प्रोडक्ट बचा है जैसे झूठे मैसेज दिखाना.

नवंबर 2023 में सरकार ने 13 ऐसे डार्क पैटर्न्स को 'अनुचित व्यापार प्रथाओं' के तहत बैन किया, जिसमें ड्रिप प्राइसिंग, झूठी जल्दबाजी, सब्सक्रिप्शन ट्रैप और छिपे हुए विज्ञापन शामिल हैं.

भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है?

2024 की ASCI रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के टॉप 53 ऐप्स में से 52 में कम से कम एक डार्क पैटर्न पाया गया. ये छिपे हुए चार्जेज, बार-बार पॉप-अप, या भ्रामक डिजाइन हो सकते हैं. खासकर ई-कॉमर्स, फिनटेक और गेमिंग ऐप्स में ये आम है. कस्टमर्स को अक्सर बाद में पता चलता है कि उन्हें ठगा गया.

सरकार क्या कर रही है?

COD चार्जेज की जांच के साथ-साथ सरकार डिजिटल फ्रॉड पर नकेल कस रही है. 28 मई को मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ मीटिंग की और उन्हें अपने ऐप्स का ऑडिट करने को कहा. साथ ही, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का प्लान है, जो इन समस्याओं पर नजर रखेगा. जांच में ये देखा जाएगा कि चार्जेज के बारे में कस्टमर्स को साफ-साफ बताया गया या नहीं.

आगे क्या होगा?

अगर कोई प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न इस्तेमाल करता पाया गया, तो उस पर जुर्माना, डिजाइन में बदलाव या सख्त नियम लागू हो सकते हैं. COD भारत में बहुत पॉपुलर पेमेंट तरीका है, खासकर छोटे शहरों में. इसलिए ये जांच बहुत अहम है. सरकार का ये कदम दिखाता है कि अब शुल्क और डिजाइन भी उतने ही सख्ती से चेक किए जाएंगे, जितना प्राइसिंग और विज्ञापन किए जाते हैं.

अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होने वाला यह शो हर हफ्ते अपनी ड्रामेटिक ट्विस्ट्स और अप्रत्याशित घटनाओं से फैंस को जोड़े रखता है.

'राइज एंड फॉल' के पेंटहाउस में हो रहा है काला जादू?

धनश्री वर्मा ने इस कंटेस्टेंट्स पर लगाए गंभीर आरोप

अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होने वाला यह शो हर हफ्ते अपनी ड्रामेटिक ट्विस्ट्स और अप्रत्याशित घटनाओं से फैंस को जोड़े रखता है.

लेकिन हाल के एपिसोड में ऐसा वाकया हुआ, जिसने न सिर्फ कंटेस्टेंट्स को बल्कि दर्शकों को भी हैरान कर दिया.

शो का सेट दो हिस्सों में बंटा है, लग्जरी पेंटहाउस और बेसमेंट. पेंटहाउस के आरामदेह माहौल में अचानक एक रहस्यमयी डर ने जगह बना ली. धनश्री वर्मा, जो पेंटहाउस में रहती हैं, उन्हें लगा कि उन पर काला जादू किया जा रहा है. यह डर तब शुरू हुआ जब आकृति नेगी रेड रूम से बाहर निकलते ही कुछ सामान लेकर अंदर गईं, जिसमें कैंडल, लाइटर, पेन और पेपर शामिल थे.

मजाक ने पकड़ी आग

बाहर खड़ी टीम, मनीषा, अरबाज, धनश्री और अर्जुन ने आकृति को देख कर कहा कि वह धनश्री पर काला जादू कर रही हैं. यह बात जैसे आग की तरह फैल गई. धनश्री घबराकर मेकर्स से लिफ्ट खोलने की गुहार लगाने लगीं और आकृति को शो से बाहर करने तक की बात करने लगीं.

सच क्या था ?

जैसे ही सच्चाई सामने आई, सब हंसी से लोटपोट हो गए. पता चला कि आकृति ने जो सामान लिए थे, उनका इस्तेमाल अपनी फैमिली के स्केच बनाने में कर रही थीं. लेकिन मजाक में अरबाज और अर्जुन ने इस डर को और बढ़ा दिया.

कैंडल बुझने की घटना ने तो धनश्री के डर को चरम पर पहुंचा दिया. अंत में अरबाज ने सबको समझाया कि यह सब सिर्फ एक मजाक था. 'राइज एंड फॉल' का ये हिस्सा न सिर्फ मजेदार था, बल्कि दर्शकों को दिखाता है कि इस शो में कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इस काला जादू के बहाने बने ड्रामे ने शो को और भी दिलचस्प बना दिया है.

जब यशराज बैनर को छोड़कर अनुष्का शर्मा ने की बाहर की फिल्म, हुआ था बहुत बुरा हाल

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. अनुष्का शर्मा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत यशराज फिल्म्स की फिल्म के जरिए की थी. करियर की शुरुआत में उन्होंने एक के बाद एक यशराज बैनर की फिल्मों में काम किया था. लेकिन, जब यशराज बैनर का दामन छोड़कर उन्होंने बाहर की पिक्चर की थी तो एक्ट्रेस को बड़ा झटका लगा था. क्योंकि उनकी वो पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी.अनुष्का शर्मा ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया था. इसी बीच उन्हें आदित्य चोपड़ा की फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' का ऑफर मिल गया था. इसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था. ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और अनुष्का अपनी पहली ही पिक्चर से छा गई थीं. इसके बाद उन्होंने 'बदमाश कंपनी' और 'बैंड बाजा बारात' में काम किया था. ये दोनों फिल्में भी यशराज बैनर की थीं.

जब अनुष्का ने की यशराज बैनर के बाहर की फिल्म

अनुष्का शर्मा ने अपने शुरुआती करियर की 6 में से पांच फिल्में यशराज बैनर की थीं. उन्होंने यशराज बैनर से बाहर जिस फिल्म में काम किया था उसका अनाम है 'पटियाला हाउस'. इसमें वो अभिनेता अक्षय कुमार के अपोजिट लीड रोल में नजर आई थीं. हालांकि एक्ट्रेस की ये पिक्चर कोई कमाल नहीं कर पाई थी.

पटियाला हाउस 11 फरवरी 2011 को रिलीज हुई थी. इसमें अक्षय और अनुष्का के साथ ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, टीनू आनंद, सोनी राजदान और प्रेम चोपड़ा जैसे मशहूर कलाकारों ने भी काम किया था. फिल्म का डायरेक्शन निखिल आडवाणी ने किया था. वहीं इसे मुकेश तलरेजा, शोएब स्प्रिंगवाला, ट्विंकल खन्ना, भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने मिलकर प्रोड्यूस किया था.

बजट भी नहीं निकाल पाई थी पटियाला हाउस

पटियाला हाउस पर मेकर्स ने 55 करोड़ रुपये का अच्छा बजट खर्च किया था. हालांकि फिल्म उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई थी. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस पिक्चर ने सिर्फ 31.17 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा 42 करोड़ रुपये रहा था. फिल्म महाफ्लॉप निकली थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने 'जब तक है जान' और 'लेडीज वर्सेज रिक्की बहल' नाम की यशराज की दो फिल्मों में काम किया और दोनों बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली थीं.

'धक्के मारकर घर से...' पत्नी आलिया के डैड से ऐसे मिले थे राहा के पापा, एक्ट्रेस ने खोला राज

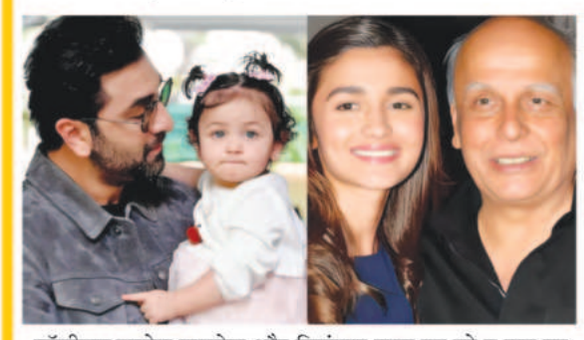

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो टू मच इन दिनों खासी सुर्खियों में है. शो का पहला एपिसोड काफी अच्छा रहा था, जहां एक्टर सलमान खान और आमिर खान ने शो में आकर खूब मस्ती की थी. अब शो का नया एपिसोड आ गया है और इस बार शो के दूसरे एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने शिरकत की.काजोल और ट्विंकल के शो में वरुण और आलिया ने खूब मस्ती की. आलिया और वरुण ने काजोल और ट्विंकल को बताया कि बीते साल उनके लिए कैसे रहे. दोनों सितारों ने एक साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और आज दोनों शादीशुदा हैं और बच्चों के माता-पिता है. पेरेंटिंग, शादी और करियर पर एक्टर्स ने खुलकर बात की.

महेश भट्ट से ऐसे मिले थे रणबीर कपूर

काजोल ने आलिया से पति रणबीर कपूर संग रिश्ते के पहले सालों के बारे में पूछा. आलिया ने उस वक्त के बारे में बात की जब उन्होंने पहली बार रणबीर के बारे में बताया. आलिया ने कहा कि उन्होंने बहुत ही सिम्पल तरीके से पापा (महेश भट्ट) को बताया था कि उनको प्यार हो गया है, और महेश ने भी उनसे कहा था कि वो उनकी आंखों में दिख रहा है. इसके बाद एक दिन जब महेश आलिया को रणबीर के घर छोड़ रहे थे, तो आलिया ने बताया कि उन्होंने रणबीर को नीचे मिलने बुलाया और वहीं पहली बार दोनों की बात हुई.

राहा-रणबीर के बॉन्ड पर आलिया

आलिया ने बताया कि रणबीर ने आते ही दोनों हाथ जोड़े और फिर महेश भट्ट के पैर छुए और महेश ने भी उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया. आलिया ने कहा कि वहां पर महेश भट्ट ने कुछ नहीं कहा और बस दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतेहा प्यार देखा. हालांकि, आलिया ने बताया कि जितना महेश उनको और रणबीर को लेकर कूल थे, उतना वो रणबीर से राहा को लेकर एक्सपेक्ट नहीं करतीं. आलिया ने कहा कि रणबीर जिस तरह से राहा को लेकर प्रोटेक्टिव हैं, उन्हें लगता है कि आगे चलकर अगर राहा किसी लड़के को रणबीर से मिलाने लाएंगीं, तो रणबीर शायद उस लड़के को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें.

राहुल के 'सीटी मार' सेलिब्रेशन पर फिदा हुई पत्नी

अथिया शेट्टी

शतक पर दिया ऐसा रिएक्शन

एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम अपने घर में वेस्टइंडीज से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. दो दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय टीम बेहद मजबूत स्थिति में है. खेल के दूसरे दिन भारत के तीन बल्लेबाजों केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल ने सेंचुरी लगाई. इनमें से राहुल के सेंचुरी लगाने के बाद का सेलिब्रेशन काफी वायरल हो रहा है. इस पर उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने भी रिएक्ट किया है.भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में सिर्फ 162 रनों पर समेट दिया था. इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और राहुल ने की. जायसवाल तो 36 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन, राहुल ने शतक जड़ दिया. शतक के बाद राहुल अंदाज में इसका जश्न मनाते हुए नजर आए. इस पर उनकी पत्नी अथिया भी फिदा हो गई.

राहुल की सेंचुरी पर क्या बोलीं अथिया ?

केएल राहुल ने अहमदाबाद टेस्ट के दौरान अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा किया है. ये शतक इसलिए भी बेहद खास है, क्योंकि राहुल ने घरेलू सरजमीं पर 9 साल बाद टेस्ट शतक लगाया है. सोशल मीडिया पर फैंस, क्रिकेटर्स और पूर्व क्रिकेटर्स उनकी इस पारी की तारीफ कर रहे हैं. वहीं अथिया ने पति की एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा है, अपने बेस्ट के लिए सबसे बेस्ट.

देखें राहुल का 'सीटी मार' सेलिब्रेशन

वेस्टइंडीज के खिलाफ राहुल ने 197 गेंदों में 100 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके निकले. शतक पूरा करने के बाद राहुल ने एक हाथ से अपना बल्ला उठाया और दूसरे हाथ से वो सीटी बजाते हुए दिखें. उनके इस नए सेलिब्रेशन को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. इसका वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक बेटी के पैरेंट्स हैं अथिया-राहुल

अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने साल 2023 में मुंबई में शादी की थी. जबकि मार्च 2025 में दोनों के घर किलकारी गूंजी थी.

शादी का झांसा देकर युवती को ब्लैकमेल करने वाला जिम ट्रेनर गिरफ्तार

कानपुर। जनपद की कमिश्ननरेट कोहना पुलिस ने जिम करने वाली महिला को शादी को झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर पहले रेप किया फिर अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता से 3.50 लाख रुपये भी ठग लिए। महिला की तहरीर पर पुलिस ने उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी कर्नलगंज अमित चौरसिया ने बताया कि कोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती इलाके में बने एक जिम में जाती थी। वहीं विनायकपुर नवीन नगर का रहने वाला दीपक कुमार गौतम जिम ट्रेनर है। शातिर ने पहले तो पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई फिर दोस्ती करते हुए उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यही नहीं युवती को विश्वास दिलाने के लिए आरोपित ने उसे अपने परिजनों से भी मिलाया। फिर उसे एक होटल में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शातिर ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। इसी वीडियो के आधार पर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। एक दिन उसने युवती से कहा कि तुम मुझे साढ़े तीन लाख रुपये दे दो तो मैं नया जिम खोल लूंगा और फिर दोनों शादी कर लेंगे। युवती ने उसे रुपये दे दिए लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं हुई और वह लगातार उसके साथ संबंध बनाता रहा। रोज रोज के टॉर्चर से तंग आकर पीड़िता ने गुरुवार को दीपक कुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मुजफ्फरनगर: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी ढेर

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में शुक्रवार की देर रात को पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश मारा गया है। इसमें दारोगा और एक सिपाही घायल हुए हैं। इस दौरान बदमाश का एक साथी भागने में सफल रहा, जिसे तलाश की जा रही है।

एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि बुढ़ाना कोतवाली और शाहपुर थाना पुलिस गुरुवार देर रात को परसौली नहर पटरी पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान नहर पटरी पर एक मोटर साइकिल पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों युवक बाइक लेकर भागने लगे। इस पर पुलिस ने उनका पीछा किया और जौला नहर पुल के पास पुराने बंद भट्टे के पास बदमाशों को घेराबंदी की तो उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसमें गढ़ी सखावत चौकी प्रभारी ललित कसाना और शाहपुर थाना में तैनात अलीम घायल हो गया।

पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी पर एसएसपी संजय कुमार मौका मुआयना किया।उन्होंने बताया कि पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश मारा गया है। उसकी शिनाख्त शामली जनपद में थानाभवन के गांव सोंटा रसूलपुर निवासी महताब (30)के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ लूट डकैती अपहरण जानलेवा हमला करना आदि मामलों में तकरीबन 18 से अधिक मुकदमे दर्ज है। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक 32 बोर का रिवाल्वर व एक 9 एमएम का पिस्टल व कारतूस व बाइक, तीन तौला सोना, एक किलो चांदी बरामद की है।

तिलक नगर पार्किंग घोटाला: एमसीडी दरों से दोगुनी वसूली का खुलासा

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट स्थित एमसीडी पार्किंग पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल, स्थानीय निवासी आशीष शर्मा ने आरोप लगाया है कि एमसीडी के तय नियमों के अनुसार दो पहिया वाहन के लिए प्रति घंटा 10 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 20 रुपये शुल्क निर्धारित है। लेकिन तिलक नगर मार्केट की इस एमसीडी पार्किंग में दोगुना शुल्क वसूला जा रहा है। आशीष शर्मा का कहना है कि कई बार लोगों ने इस मनमानी वसूली की शिकायत की, लेकिन न तो पार्किंग ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई और न ही एमसीडी की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया।

लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर, अहरौरा और जरगो जलाशय के गेट खोले गए

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते अहरौरा और जरगो जलाशयों का जलस्तर क्षमता से अधिक हो गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शनिवार सुबह अहरौरा जलाशय के आठ गेट दो-दो फीट तक खोल दिए गए। इसके माध्यम से लगभग चार हजार क्यूसेक प्रति सेकेंड की दर से पानी की निकासी की जा रही है। अहरौरा बांध की अधिकतम क्षमता 360 फीट है, जबकि शनिवार सुबह आठ बजे तक जलस्तर 360.07 फीट दर्ज किया गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए और गेट खोले जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे जमालपुर क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहीं, जरगो जलाशय का जलस्तर भी 320 फीट की निर्धारित क्षमता से ऊपर पहुंच गया है।

आगामी 14 अक्टूबर तक बढ़ाया गया आवास सर्वे का कार्य, नये लाभार्थी कराये अपना डाटा कैप्चर

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 में नये लाभार्थियों का डाटा कैप्चर करने के लिए समय सीमा 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ायी गयी है। शुक्रवार को जानकारी देते हुए डीआरडीए परियोजना निदेशक शेषमणि सिंह ने बताया कि यदि पात्र लाभार्थी किसी कारण से सर्वे मे आने से छूट गये है या सर्वे के समय घर पर उपलब्ध नही थे तथा वर्तमान में घर मे आ गये है तो ऐसे लाभार्थियों का सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 14 अक्टूबर 2025 तक सभी ग्राम पंचायतों मे अनिवार्य रुप से पूर्ण किया जाना है।

दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर संत-महंतों के साथ प्रशासन ने की बैठक

अयोध्या। प्रशासन ने दीपोत्सव की भव्यता और व्यवस्था को लेकर तैयारियाँ तेज कर दी हैं। दीपोत्सव को लेकर शुक्रवार को तुलसी स्मारक भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर की उपस्थिति रही। बैठक में राम नगरी के संत-महंतों एवं विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया और दीपोत्सव की समुचित व्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। इसमें श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन, पंचकोशी व 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की स्थिति, तथा संतों के लिए कार्यक्रम स्थल पर दीर्घा आरक्षित करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि इस बार का दीपोत्सव पिछले वर्षों से अधिक दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने व्यापार मंडल से सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि व्यापारीजन दीपोत्सव को और भी सुंदर बनाने में अपना योगदान दें।विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आश्वस्त किया कि संत-महंतों द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाया जाएगा ताकि यह आयोजन एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव बने।जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि राम की पैड़ी पर दर्शन दीर्घा में आम श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संतों के सुझावों का सम्मान करते हुए व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है।बैठक में उपस्थित प्रमुख संत-महंतों में महंत करूणा निधान शरण, महंत रामलखन दास, शशिकांत दास, बालमुकुन्द शरण, जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य, और अन्य संतगण शामिल रहे। साथ ही नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह, तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

दीक्षांत समारोह में 79 मेधावियों को 80 स्वर्ण पदक

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 29वें दीक्षांत समारोह छह अक्तूबर को है। इसकी अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदी पटेल करेंगी। इसकी तैयारी बैठक को लेकर कुलपति ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक ली।छात्रों को दिए जाने वाले पदक के बारे में जानकारी देते हुए कुल सचिव केश लाल ने बताया कि पीयू विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में इस बार कुल 444 शोधार्थियों को पीएच.डी. एवं डी.लिट. की उपाधि प्रदान की जाएगी। इनमें 291 पुरुष और 155 महिलाएँ शामिल हैं। शोध उपाधियों के संकायवार वितरण पर नजर डालें तो कला संकाय सबसे आगे है, जहाँ 328 शोधार्थियों को उपाधि दी जाएगी। इसके बाद शिक्षा संकाय के 46, विज्ञान संकाय के 27 और कृषि संकाय के 11 शोधार्थियों को यह सम्मान प्राप्त होगा। इसी तरह वाणिज्य संकाय से 8, प्रबंध अध्ययन संकाय (पीएचडी एवं डी.लिट.) से 10, औषध संकाय से 4, विधि से पांच और इंजीनियरिंग संकाय से 6 तथा अनुप्रयुक्त समाज विज्ञान एवं मानविकी संकाय से 1 शोधार्थी उपाधि मिलेगी। कुल 444 शोध उपाधियों में से पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने वाले पुरुषों की संख्या 290 और महिलाओं की संख्या 154 है।

रसोई गैस लीकेज से घर में लगी भीषण आग, पांच झुलसे

गौतमबुद्ध नगर। थाना फेस- 2 क्षेत्र के भंगेल गांव के एक घर में शुक्रवार की रात को रसोई गैस सिलिंडर में लीकेज होने से आग लग गई। भीषण आग से घर के अंदर परिवार के लोग फंस गए लेकिन जैसे तैसे लोगों को घर निकाला गया।आग से पांच लोग झुलस गए। घायलों को सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने बड़ी

मशक्कत से आग पर काबू पाया।

मुख्य दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि भंगेल गांव में पिलर नंबर 128 के सामने वाली गली में 55 वर्षीय हरिमोहन व्यास का परिवार तीसरी मंजिल पर किराए के मकान में रहते हैं। शुक्रवार देर शाम को खाना बनाने के दौरान रसोई गैस के सिलिंडर से गैस लीकेज हो गई। उस वक्त घर के लोग व्यस्त थे। इस कारण कुछ देर तक गैस निकलने के बाद पता चला। तब तक घर में गैस भरने से आग लग गई। आग लगते ही तेज लपटें निलकने लगी और घर के अंदर रखे सामान को आग ने पकड़ लिया। आग लगते ही घर में अफरा-तफरी व चीख पुकार मच गई। आग फैलने से घर के लोग कुछ देर के लिए अंदर ही फंस गए और पांच लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की सूचना पर अग्निशमन की टीम दमकल गाड़ी के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू कर लिया है। प्राथमिक जांच में सिलिंडर से गैस लीकेज होने के बाद आग लगी है। उन्होने बताया कि आग लगने से 55 वर्षीय हरिमोहन व्यास, उनकी पत्नी 50 वषीर्या राजकुमारी और तीन बेटे 25 वर्षीय सचिन, 22 वर्षीय शिवम व 19 वर्षीय हिमांशु झुलस गए। तृतीय मंजिल पर हरिमोहन व्यास के घर में आग लगने से आसपास के मकानों के लोग भी घबरा गए और अपने घरों से निकल।

किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप,8 पर मुकदमा

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के बाबरपुर कस्बे के एक मुहल्ला निवासी महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है तीन अलग अलग जगहों पर अलग अलग सात लोगों ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।

महिला की 15 वर्षीय किशोरी बीते साल कक्षा 10 की छात्रा थी। बीते एक वर्ष पहले मुहल्ले के ही एक लड़के ने किशोरी से, उसका मोबाइल नम्बर किसी अन्य साथी को देने और बात कर लेने के लिए कहा। बातचीत शुरू हुई तो इटावा नुमाइश देखने का प्रोग्राम बन गया। किशोरी अपनी बहिन व अन्य बहिन और दोनों लड़कों के साथ इटावा नुमाइश देखने गई। एक होटल में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। हालत बिगडी तो कमरे में ले गए। बहिनें बाहर ही रुककर खडी रही। किशोरी को होश आया। आरोप है दोनों लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म कर लिया। और कपड़े उतारकर वीडियो बना लिया। फिर किशोरी , बाहर खडी बहिनों के साथ घर आ गई। और किसी को कुछ नहीं बताया।

पुनः वीडियो वायरल की धमकी देकर इटावा ले गए। जहाँ उन दोनों के अलावा दो अन्य लड़के भी मिले। सभी ने दुष्कर्म किया। बीते तीन महीने पहले बाबरपुर कस्बे में ही एक घर में बुलाया। जहाँ मकान मालिक सहित दो अन्य लोगो ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपये ले लिए। पुनः 10 हजार रुपये मांगे तो किशोरी ने मना कर दिया। कुछ दिनों पहले किशोरी के अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दिये। जानकारी होने पर किशोरी के ताऊ के लड़के ने किशोरी से मोबाइल लेकर सभी डाटा डिलीट कर दिया। ताकि आरोपितों को बचाया जा सके।

कोतवाल ललितेश त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर बाबरपुर कस्बे के ही अलग अलग मुहल्लों के आठ लोगों में, हिमांशु, अभय, प्रांशु, संतोष, शिवभूषण, प्रिंस, विशाल और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

प्रयागराज: जहरीला पदार्थ खाने से प्रेमी की मौत, प्रेमिका अस्पताल में भर्ती

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित सराय ममरेज थाना क्षेत्र में मरों पेट्रोल पम्प के समीप शुक्रवार रात प्रेमी की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। जबकि उसकी प्रेमिका का उपचार किया जा है। पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि मृतक शिवम मौर्य 22 वर्ष सराय ममरेज थाना क्षेत्र के मवैया हिन्दू वाहिनी गांव का निवासी है। परिवार से तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी गंगानगर ने बताया कि 2 अक्टूबर को सराय ममरेज थाने में एक महिला ने तहरीर देकर सूचना दी थी कि मवैया हिन्दू वाहिनी गांव निवासी शिवम मौर्य उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने इस संबंध में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश कर रही थी। शुक्रवार देर शाम सूचना मिली कि सराय ममरेज थाना क्षेत्र में स्थित मरों पेट्रोल पम्प के पास एक प्रेमी प्रेमिका ने जहर खा लिया है। इस सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को उपचार के लिए तत्काल स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने शिवम मौर्य को मृत घोषित कर दिया और युवती का उपचार शुरू कर दिया।

पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि लड़की के घर वाले शादी करने का विरोध कर रहे थे।जिसकी वजह से दोनों घर छोड़कर भाग निकले थे। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई थी।

लखनऊ: एक युवक समेत दो लोगों ने की आत्महत्या

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में शनिवार को एक युवक समेत दो लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिगांव थानाध्यक्ष शिव मंगल सिंह ने बताया कि भिखारीपुर गांव निवासी महेंद्र (25) पुत्र नरेश का शव शनिवार सुबह घर से पांच सौ मीटर दूर राकेश के खेत में नीम के पेड़ से लटका मिला। स्थानीय निवासियों की सूचना पर पुलिस की फील्ड यूनिट ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थानाध्यक्ष ने बताया कि परिजनों से पूछताछ की गई, लेकिन बेटे के फांसी लगाए जाने के बारे में उन्हें

बारिश के बीच अमन चैन के लिए सीपी फोर्स के साथ सड़क पर उतरे, पैदल रूट मार्च

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुक्रवार को दुर्गा प्रतिमा विर्सजन,जुमे की नमाज और नाटी इमली के विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट मोहित अग्रवाल बारिश के बावजूद फोर्स के साथ सड़क पर डटे रहे। उन्होंने फोर्स के साथ संवेदनशील दालमंडी क्षेत्र से श्री काशी विश्वनाथ धाम होते हुए गोदौलिया तक पैदल रूट मार्च किया। रूट मार्च के दौरान उन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण की स्थिति का निरीक्षण करते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने नागरिकों, व्यापारियों एवं श्रद्धालुओं से संवाद कर सहयोग एवं अनुशासन बनाए रखने की अपील की। उन्होंन पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि त्यौहारों एवं विशेष आयोजनों के दृष्टिगत वाराणसी पुलिस पूर्ण सतर्कता और चौकसी के साथ कार्य कर रही है। रूट मार्च, सीसीटीवी/ड्रोन निगरानी, क्यूआरटी टीम, रूफटॉप ड्यूटी और व्यापक पुलिस बल की तैनाती के माध्यम से शहर में सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

पूरे शहर में हाई अलर्ट

सीपी के अनुसार दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, भरत मिलाप तथा शुक्रवार की जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए वाराणसी पुलिस पूर्णतः हाई अलर्ट पर है। शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहकर कानून-व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। नाटी इमली के ऐतिहासिक भरत मिलाप में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष पुलिस व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती रही। पूरे मार्ग व संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी रखी गई ।

लूट के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में न्यायालय ने शुक्रवार की लूट के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी के गांव गढ़ी भूपाल

निवासी किशनपाल के साथ बाइक सवार बदमाशों ने ठाकुर गजेन्द्र सिंह के नलकूप के समीप लूट को अंजाम दिया था। बदमाश उसके हाथ से नोटों का थेला लूट कर ले गए थे। बैग में 78000 रुपए थे। पुलिस ने 23 अगस्त को अभियुक्त राजू उर्फ पुराने पुत्र अमर सिंह निवासी नगला भोले फरिहा को पकड़ लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at Dinesh Sharma 19, DSIDC Sheds, Scheme 3, Okhla Phase-2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321